सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 143, नई दिल्ली, शुक्रवार 01 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दृढ़ता है...

03 दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, एस.बी.के. सिंह को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी

06 एमबीबीएस का विकल्प

08 स्तनपान सप्ताह: संकोच तोड़ने और सम्मान जोड़ने का अभियान

चालक को प्रताडित करके आत्महत्या करने पर मजबूर करना

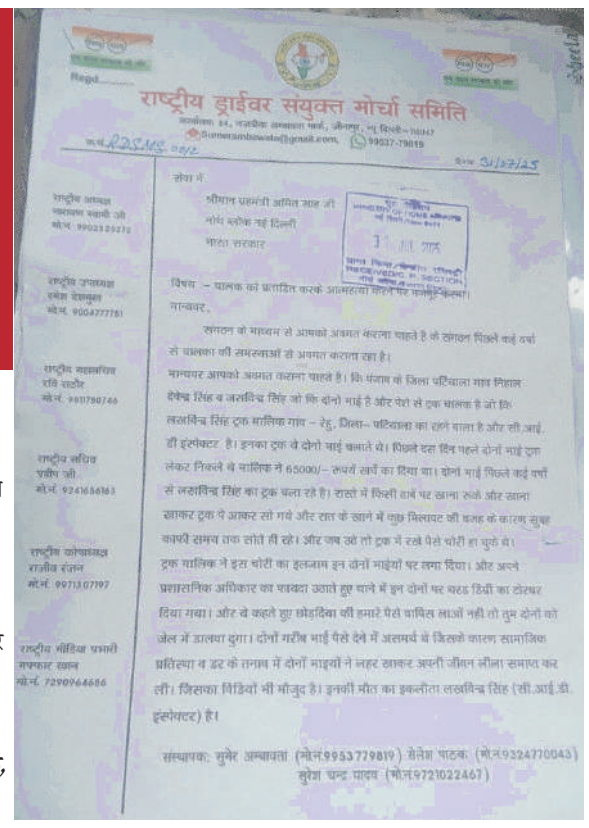
राष्ट्रीय ड्राईवर संयुक्त मोर्चा समिति

विषय – चालक को प्रताडित करके आत्महत्या करने पर मजबूर करना।

मान्यवर,

संगठन को माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते है के संगठन पिछले कई वर्षो से चालका की समस्याओं से अवगत कराता रहा है।

मान्यवर आपको अवगत कराना चाहते है। कि पंजाब के जिला पटियाला गाव निहाल देवेन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह जो कि दोनों भाई है और पेशे से ट्रक चालक है जो कि लखविन्द्र सिंह ट्रक मालिक गांव रेहु, जिला- पटियाला का रहने वाला है और सी.आई. डी इंस्पेक्टर है। इनका ट्रक ये दोनो भाई चलाते थे। पिछले दस दिन पहले दोनों माई ट्रक लेकर निकले थे मालिक ने 65000/- रूपये खर्च का दिया था। दोनों माई पिछले कई वर्षों से लखविन्द्र सिंह का ट्रक चला रहे है। रास्ते में किसी बाबें पर खाना रूके और खाना खाकर ट्रक पे आकर सो गये और रात के खाने में कुछ मिलावट की वजह के कारण सुबह काफी समय तक सोते ही रहे। और जब उठे तो ट्रक में रखे पैसे चोरी हा चुके थे। ट्रक मालिक ने इस चोरी का इलजाम इन दोनों भाईयों पर लगा दिया। और अपने प्रशासनिक अधिकार का फायदा उठाते हुए थाने में इन दोनों पर थरड डिग्री का दोरघर दिया गया। और ये कहते हुए छोड़दिया की हमारे पैसे वापिस लाओं नहीं तो तुम दोनों को जेल में डालवा दूंगा। दोनों गरीब भाई पैसे देने में असमर्थ थे जिसके कारण सामाजिक प्रतिस्था व डर के तनाव में दोनों माइयों ने लहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसका विडियों भी मौजुद है। इनकी मौत का इकलौता लखविन्द्र सिंह (सी.आई.डी. इंस्पेक्टर) है।

संस्थापक: सुमेर अम्बावता (मो.नं.9953779819) सेलेश पाठक (मो.नं.9324770043) सुरेश चन्द्र यादव (मो.नं.9721022467)

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

संगठन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते है के संगठन पिछले कई वर्षों से चालका की समस्याओं से अवगत कराता रहा है। आपको अवगत कराना चाहते है। कि पंजाब के जिला पटियाला गाव निहाल देवेन्द्र सिंह व जसविन्द्र सिंह जो कि दोनों भाई है और पेशे से ट्रक चालक है जो कि लखविन्द्र सिंह ट्रक मालिक गांव रेहु, जिला- पटियाला का रहने वाला है और सी.आई. डी इंस्पेक्टर है। इनका ट्रक ये दोनो भाई चलाते थे। पिछले दस दिन पहले दोनों माई ट्रक लेकर निकले थे मालिक ने 65000/- रूपये खर्च का दिया था। दोनों माई पिछले कई वर्षों से लखविन्द्र सिंह का ट्रक चला रहे है। रास्ते में किसी बाबें पर खाना रूके और खाना खाकर ट्रक पे आकर सो गये और रात के खाने में कुछ मिलावट की वजह के कारण सुबह काफी समय तक सोते ही रहे। और जब उठे तो ट्रक में रखे पैसे चोरी हा चुके थे। ट्रक मालिक ने इस चोरी का इलजाम इन दोनों भाईयों पर लगा दिया। और अपने प्रशासनिक अधिकार का फायदा उठाते हुए थाने में इन दोनों पर थरड डिग्री का दोरघर दिया गया। और ये कहते हुए छोड़दिया की हमारे पैसे वापिस लाओं नहीं तो तुम दोनों को जेल में डालवा दूंगा। दोनों गरीब भाई पैसे देने में असमर्थ थे जिसके कारण सामाजिक प्रतिस्था व डर के तनाव में दोनों माइयों ने लहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसका विडियों भी मौजुद है। इनकी मौत का इकलौता लखविन्द्र सिंह (सी.आई.डी. इंस्पेक्टर) है।

सुमेर अम्बावता, सेलेश पाठक, सुरेश चन्द्र यादव

परिवहन के द्वारा रोजाना कई सौ करोड़ों के जीएसटी इनपुट फर्जी वाड़े को अमली जामा पहनाया जा रहा -केवल बिहार में : डॉ राजकुमार यादव

– एक बिल पर एक से अधिक बार माल परिवहन - ,अंडरलोड के चालान किंतु माल दुगनी (जी एस टी बिल के बिना)

पटना - रा सँ मो (उफ्तत्सा),बिहार राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा,झारखंड और पश्चिम बंगाल से रोजाना माल परिवहन के बहाने कई सौ करोड़ की जीएसटी चोरी लगातार की जा रही है 1 संलग्न विभाग के फील्ड ऑफीसरों के सँरक्षण के बिना यह कतई संभव नहीं, उस पर से रंग चढ़ाते आरटीओ / डीटीओ (परिवहन अधिकारी) खुले तौर पर शामिल 1 परिवहन अधिकारी इसमें संलिप्त गाड़ियों से एंट्री लेने के पश्चात बेसुध हो जाते हैं व उसमें किस तरह का माल जा रहा है और अधिकृत/स्वीकृत वजन से कहीं अधिक माल की धुलाई लगातार जारी है1 स्पंज आयरन, एम एस बिलेट,पिग आयरन, टी एम टी,एम एस सक्रेप, एमएस वायर व अधिकांशतः अन्य लोहे की सामग्री का परिवहन धड़ल्ले से जारी है बिना फर्जी वाड़े के काम करने वालों को आज काम मिलने तक में भी दिक्कत आने लगी है जिससे फर्जी जीएसटी इनपुट धंधा अपने चरम पर है व लगातार फल फूल रहा है 1 राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि शीघ्रता शीघ्र इसमें नकेल कसने की तैयारी कर ली है एंव इनसे जुड़े गाड़ियों के नम्बर, ट्रेडर्स,संयत्रों, व्यापारीयों सह अन्य की सूची माननीय मुख्यमंत्री सह केंद्र सरकार के वित्त मंत्री को व संलग्न विभागीय वरिष्ठ अधिकारीयों को सौंपेगी 1 केंद्र सहित राज्य सरकार को रोजाना कई 100 करोड़ के राजस्व का नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है व अधिकारी बेसुध स्थिति में पड़े हैं 1 शीघ्रता शीघ्र इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है अन्यथा सामान्य व्यापारी व सामान्य परिवहन उद्योग से जुड़े व्यवसायी को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है व उनका मनोबल लगातार गिर रहा है 1 जहां एक ओर परिवहन उद्योग कई तरह के जीएसटी स्लैब से जुडी समस्याओं से जूझ रहा है वहीं फर्जी जीएसटी इनपुट के कारण गाड़ी मालिकों को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है व माल के लिए चेहरा तक ताकना पड़ रहा है लेकिन जो परिवहन व्यवसायी फर्जी जीएसटी इनपुट के खेल में व्यवसाइयों,ट्रेडर्स, फैक्ट्री मालिकों व इस सिण्डिकेट के साथ मिले हुए हैं उनकी गाड़ियों के रिकॉर्ड देखे जाएं तो 30 के 30 दिन वें बेधड़क सड़क पर दौड़ते नजर आएंगे लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामान्य मोटर मालिक के गाड़ी माल के लिए हफ़्तों तरसते नजर आ रहे हैं 1 परिवहन उद्योग की दुरावस्था सारथी समाज (चालक), सामान्य मोटर मालिक एंव पूरी ईमानदारी से काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों को इस अवस्था में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार व सरकारी तंत्र कहीं न कहीं सीधे तौर पर जिम्मेदार है,यही वजह है कि इस जंग से लड़ने की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) ₹उफतत्सा₹ ने उठाई है व पूरी ईमानदारी से इस तालमेल (नेटवर्क) को तोड़ने की जिम्मेदारी लेती है, आने वाले समय में बिहार में जिस तरह ओवरलोड पर लगाम लगा है व अन्य अनीमियताओं पर रोक लगी है, फर्जी जीएसटी इनपुट का मामला भी निश्चित रूप से दम तोड़ेगा ऐसी उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है -शीघ्र ही इस तरह के सिंडिकेट के खेल को उजागर करने की जिम्मेदारी लेने के लिए संस्था ने कमर कस ली है।

दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तीन कॉरिडोर पर दौड़ेंगी तिरंगा थीम ट्रेनें, ड्राइवरलेस से तेज स्पीड तक ये होंगी खूबियां

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में नई ट्रेनों में तिरंगे का थीम होगा। छह कोच वाली इन ट्रेनों का निर्माण भारत में ही हो रहा है जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। पुरानी ट्रेनों के मुकाबले ये अधिक तेज रफ्तार से चलेंगी और ध्वनि प्रदूषण भी कम करेंगी। यात्रियों के लिए मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

नईदिल्ली। फेज चार की नई चालक रहित Metro ट्रेनों में तिरंगे की थीम दिखेगी। छह कोच के इन मेट्रो ट्रेनों के पहला कोच के अंदर केसरिया, दूसरे में सफेद और तीसरे में हरे रंग का थीम होगा। इसी तरह चौथे, पांचवें व छठे कोच में भी क्रमशः केसरिया, सफेद व हरे रंग का थीम होगा, इसलिए पूरी तरह देश में निर्मित फेज चार की मेट्रो ट्रेनें राष्ट्र भावना को प्रेरित करेंगी।

अभी तक फेज चार की एक मेट्रो ट्रेन दिल्ली पहुंची है। इसका मुकुंदपुर डिपो में ट्रायल चल रहा है। जल्दी ही ये ट्रेन मेट्रो कॉरिडोर पर रफ्तार भर सकती है।

आंध्र प्रदेश में चल रहा कोच का निर्माण

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) फेज चार के लिए छह कोच की 52 ट्रेनें (352 कोच) खरीद रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीसिटी में इन ट्रेनों का निर्माण चल रहा है।

ये ट्रेनें कई मामलों में पुरानी ट्रेनों से अलग होंगी। ये ट्रेनें पुरानी मेट्रो ट्रेनों की तुलना में तेज गति से रफ्तार भर सकेंगी। साथ ही परिचालन के दौरान इन ट्रेनों से शोर भी कम होगा।

इसलिए ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा फेज तीन की वर्तमान स्वचालित मेट्रो ट्रेनों की तरफ फेज चार की नई मेट्रो ट्रेनों के कोच की सीट रंग बिरंगी नहीं होगी। सभी कोच में यात्रियों के मोबाइल व लैपटाप चार्जिंग की सुविधा होगी।

फेज-चार के तहत बन रहे ये कॉरिडोर

फेज चार में जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर, मौजपुर-मजिलिस पार्क कॉरिडोर व गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी) कॉरिडोर बन रहा है।

मौजपुर-मजिलस पार्क कॉरिडार बनकर तैयार हो चुका है। यह पिंक लाइन की विस्तार परियोजना है। इस कॉरिडोर के पांच स्टेशनों के फिनिशिंग का काम चल रहा है।

इस कॉरिडोर पर मजलिस पार्क से जगतपुर गांव के बीच कॉरिडोर पर मेट्रो का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। मेट्रो का परिचालन शुरू होने का इंतजार है।

जल्द ही इस कॉरिडोर पर शुरू होगी मेट्रो

जल्द ही इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो सकता है और इस पर नई मेट्रो ट्रेन भी रफ्तार भर सकती है। जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान मजेंटा लाइन की विस्तार परियोजना है।

इस कॉरिडोर पर जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू हो चुका है। दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक एलिवेटेड कॉरिडार का ढांचा भी तैयार हो चुका है।

डीएमआरसी के अनुसार मजेंटा लाइन के कॉरिडोर पर 24 नई ट्रेनें (144 नए कोच), पिंक लाइन के कॉरिडोर पर 15 ट्रेनें (90 नए कोच) व गोल्डन लाइन पर 13 ट्रेनें (78 नए कोच) इस्तेमाल होंगी।

ये ट्रेनें मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देंगी। इन ट्रेनों की अधिकतम गति 95 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिचालन हो सकेगा। फेज तीन की स्वचालित मेट्रो ट्रेनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है।

फेज चार की नई ट्रेनों की अन्य विशेषताएं होंगी

हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे इस्तेमाल होंगे।

एचवीएसी (हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडिशनर) को यात्रियों की अधिकतम सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। ऊर्जा खपत ज्यदा नहीं होगी।

ट्रेन में सभी प्रोपल्शन उपकरण देश में डिजाइन व निर्मित हैं।

कोच में प्रयुक्त सभी सामग्री का चयन सावधानी से किया गया है ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हो।

यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्प्ले यूनिट अधिक लगाई गई है।

।। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ।।

उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है।

यह एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से सम्बंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित है जो इस प्रकार है।

शिव पुराण की 'कोटि-रुद्र संहिता' के सोलहवें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूतजी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे।

वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे।

हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम 'वेदप्रिय' था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा-परायण ही चार पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता-पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम 'देवप्रिय', 'प्रियमेधा', 'संस्कृत' और 'सुवृत' थे।

उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर 'दूषण' नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अन्त में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवन्ति (उज्जैन) के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी।

उस असुर की आज्ञा से चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकाल की आग के समान प्रकट हो गये। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मणबन्धु भयभीत नहीं हुए।

अवन्ति नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिवभक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा- 'आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें।' उसके बाद वे चारों ब्राह्मण-बन्धु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गये।

सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुँच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बाँधकर मार डालो।

वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डाँट-डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया।

उसने ज्योंही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्योंही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गम्भीर आवाल के साथ एक गडढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गये।

दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्त्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा- 'अरे दुष्टों! तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं 'महाकाल' प्रकट हुआ हूँ।

इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुँकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अन्धकार छँट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गये।

देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी दन्दुभियाँ बजायीं और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिवभक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि 'मै महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो।'

महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा- 'दुष्टों को दण्ड देने वाले महाकाल! शम्भो! आप हम सबको इस संसार-सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव! आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभो! आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें।'

भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गये। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग तीन-तीन किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।

शिवभक्त राजा चंद्रसेन और बालक की कथा-

उज्जयिनी नगरी में महान शिवभक्त तथा जितेन्द्रिय चन्द्रसेन नामक एक राजा थे। उन्होंने शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन कर उनके रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनके सदाचरण से प्रभावित होकर शिवजी के पार्षदों (गणों) में अग्रणी (मुख्य) मणिभद्र जी राजा चन्द्रसेन के मित्र बन गये।

मणिभद्र जी ने एक बार राजा पर अतिशय प्रसन्न होकर राजा चन्द्रसेन को चिन्तामणि नामक एक महामणि प्रदान की। वह महामणि कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान (चमकदार) थी। वह महा मणि देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी, वह मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी।

राजा चन्द्रसेन के गले में अमूल्य चिन्तामणि शोभा पा रही है, यह जानकार सभी राजाओं में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। चिन्तामणि के लोभ से सभी राजा क्षुभित होने लगे। उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिणी सेना तैयार की और उस चिन्तामणि के लोभ में वहाँ आ धमके।

चन्द्रसेन के विरुद्ध वे सभी राजा एक साथ मिलकर एकत्रित हुए थे और उनके साथ भारी सैन्यबल भी था। उन सभी राजाओं ने आपस में परामर्श करके रणनीति तैयार की और राजा चन्द्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों सहित उन राजाओं ने चारों ओर से उज्जयिनी के चारों द्वारों को घेर लिया।

अपनी पुरी को चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चन्द्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुँच गये। वे निश्छल मन से दृढ़ निश्चय के सथ उपवास-व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में जुट गये।

उन दिनों उज्जयिनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी, जिसको इकलौता पुत्र था। वह इस नगरी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने उस पाँच वर्ष के बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने हेतु गई। उस बालक ने देखा कि राजा चन्द्रसेन वहाँ बड़ी श्रद्धाभक्ति से महाकाल की पूजा कर रहे हैं।

राजा के शिव पूजन का महोत्सव उसे बहुत ही आश्चर्यमय लगा। उसने पूजन को निहारते हुए भक्ति भावपूर्वक महाकाल को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर लौट गयी। उस ग्वालिन माता के साथ उसके बालक ने भी महाकाल की पूजा का कौतूहलपूर्वक अवलोकन किया था।

इसलिए घर वापस आकर उसने भी शिव जी का पूजन करने का विचार किया। वह एक सुन्दर-सा पत्थर ढूँढ़कर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकान्त में रख दिया।

उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। वह शुद्ध मन से भक्ति भावपूर्वक मानसिक रूप से गन्ध, धूप, दीप, नैवेद्य और अलंकार आदि जुटाकर, उनसे उस शिवलिंग की पूजा की। वह सुन्दर-सुन्दर पत्तों तथा फूलों को बार-बार पूजन के बाद उस बालक ने बार-बार भगवान के चरणों में मस्तक लगाया।

बालक का चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था और वह विह्वल होकर उनको दण्डवत कर रहा था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया। उधर उस बालक का मन शिव जी की पूजा में रमा हुआ था, जिसके कारण वह बाहर से बेसुध था। माता द्वारा बार-बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई और वह भोजन करने नहीं गया तब उसकी माँ स्वयं उठकर वहाँ आ गयी।

माँ ने देखा कि उसका बालक एक पत्थर के सामने आँखें बन्द करके बैठा है। वह उसका हाथ पकड़कर बार-बार खींचने लगी पर इस पर भी वह बालक वहाँ से नहीं उठा, जिससे उसकी माँ को क्रोध आया और उसने उसे ख़ूब पीटा। इस प्रकार खींचने और मारने-पीटने पर भी जब वह बालक वहाँ से नहीं हटा, तो माँ ने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया।

बालक द्वारा उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सामग्री को भी उसने नष्ट कर दिया। शिव जी का अनादर देखकर बालक 'हाय-हाय' करके रो पड़ा। क्रोध में आगबबूला हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डाँट-फटकार कर पुनः अपने घर में चली गई।

जब उस बालक ने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा को उसकी माता ने नष्ट कर दिया, तब वह बिलख-बिलख कर रोने लगा।

देव! देव! महादेव! ऐसा पुकारता हुआ वह सहसा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई। कुछ देर बाद जब उसे चेतना आयी, तो उसने अपनी बन्द आँखें खोल दीं।

उस बालक ने आँखें खोलने के बाद जो दृश्य देखा, उससे वह आश्चर्य में पड़ गया। भगवान शिव की कृपा से उस स्थान पर महाकाल का दिव्य मन्दिर खड़ा हो गया था। मणियों के चमकीले खम्भे उस मन्दिर की शोभा बढा रहे थे। वहाँ के भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गयी थी।

तपाये गये दमकते हुए स्वर्ण-शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उस मन्दिर के विशाल द्वार, मुख्य द्वार तथा उनके कपाट सुवर्ण निर्मित थे। उस मन्दिर के सामने नीलमणि तथा हीरे जड़े बहुत से चबूतरे बने थे।

उस भव्य शिवालय के भीतर मध्य भाग में (गर्भगृह) करुणावरुणालय, भूतभावन, भोलानाथ भगवान शिव का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित हुआ था।

ग्वालिन के उस बालक ने शिवलिंग को बड़े ध्यानपूर्वक देखा उसके द्वारा चढ़ाई गई सभी पूजन-सामग्री उस शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी हुई थी। उस शिवलिंग को तथा उसपर उसके ही द्वारा चढ़ाई पूजन-सामग्री को देखते-देखते वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन आश्चर्य तो बहुत हुआ, किन्तु वह परमान्द सागर में गोते लगाने लगा। उसके बाद तो उसने शिव जी की ढेर-सारी स्तुतियाँ कीं और बार-बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया।

उसके बाद जब शाम हो गयी, तो सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से निकल कर बाहर आया और अपने निवास स्थल को देखने लगा। उसका निवास देवताओं के राजा इन्द्र के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ शीघ्र ही सुवर्णमय हो गया था, जिससे वहाँ की विचित्र शोभा हो गई थी।

परम उज्ज्वल वैभव से सर्वत्र प्रकाश हो रहा था। वह बालक सब प्रकार की शोभाओं से सम्पन्न उस घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसने देखा कि उसकी माता एक मनोहर पलंग पर सो रही हैं। उसके अंगों में बहुमूल्य रत्नों के अलंकार शोभा पा रहे हैं।

आश्चर्य और प्रेम में विह्वल उस बालक ने अपनी माता को बड़े ज़ोर से उठाया। उसकी माता भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर चुकी थी। जब उस ग्वालिन ने उठकर देखा, तो उसे सब कुछ अपूर्व 'विलक्षण' सा देखने को मिला। उसके आनन्द का ठिकाना न रहा।

उसने भावविभोर होकर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। अपने बेटे से शिव के कृपा प्रसाद का सम्पूर्ण वर्णन सुनकर उस ग्वालिन ने राजा चन्द्रसेन को सूचित किया। निरन्तर भगवान शिव के भजन-पूजन में लगे रहने वाले राजा चन्द्रसेन अपना नित्य-नियम पूरा कर रात्रि के समय पहुँचे। उन्होंने भगवान शंकर को सन्तुष्ट करने वाले ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा।

उज्जयिनी को चारों ओर से घेर कर युद्ध के लिए खड़े उन राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से प्रातःकाल उस अद्भुत वृत्तान्त को सुना। इस विलक्षण घटना को सुनकर सभी नरेश आश्चर्यचकित हो उठे। उन राजाओं ने आपस में मिलकर पुनः विचार-विमर्श किया।

परस्पर बातचीत में उन्होंने कहा कि राजा चन्द्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। ये सभी प्रकार से निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जयिनी का पालन-पोषण करते हैं। जब इस नगरी का एक छोटा बालक भी ऐसा शिवभक्त है, तो राजा चन्द्रसेन का महान शिवभक्त होना स्वाभाविक ही है।

ऐसे राजा के साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित हो जाएँगे। शिव के क्रोध करने पर तो हम सभी नष्ट ही हो जाएँगे। इसलिए हमें इस नरेश से दुश्मनी न करके मेल-मिलाप ही कर लेना चाहिए, जिससे भगवान महेश्वर की कृपा हमें भी प्राप्त होगी।

युद्ध के लिए उज्जयिनी को घेरे उन राजाओं का मन भगवान शिव के प्रभाव से निर्मल हो गया और शुद्ध हृदय से सभी ने हथियार डाल दिये। उनके मन से राजा चन्द्रसेन के प्रति बैर भाव निकल गया और उन्होंने महाकालेश्वर पूजन किया। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान वहाँ प्रकट हो गये।

उन्होंने गोप-बालक को अपने हृदय से लगाया और राजाओं की ओर देखते हुए कहा- 'राजाओं! तुम सब लोग तथा अन्य देहधारीगण भी ध्यानपूर्वक हमारी बातें सुनें। मैं जो बात कहूँगा उससे तुम सब लोगों का कल्याण होगा।

उन्होंने बताया कि 'शरीरधारियों के लिए भगवान शिव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है अर्थात महेश्वर की कृपा-प्राप्ति ही मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि इस गोप कुमार ने शिवलिंग का दर्शन किया और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव की पूजा में प्रवृत्त हुआ।

यह बालक किसी भी प्रकार का लौकिक अथवा वैदिक मन्त्र नहीं जानता है, किन्तु इसने बिना मन्त्र का प्रयोग किये ही अपनी भक्ति निष्ठा के द्वारा भगवान शिव की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। यह बालक अब गोप वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला तथा उत्तम शिवभक्त हो गया है।

भगवान शिव की कृपा से यह इस लोक के सम्पूर्ण भोगों का उपभोग करेगा और अन्त में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बालक के कुल में इससे आठवीं पीढ़ी में महायशस्वी नन्द उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ ही साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव होगा।

वे भगवान नारायण ही नन्द के पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्रीकृष्ण के नाम से जगत में विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी, जिस पर कि भगवान शिव की कृपा हुई है, 'श्रीकर' गोप के नाम से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा।

शिव के ही प्रतिनिधि वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं सहित राजा चन्द्रसेन को अपनी कृपादृष्टि से देखा। उसके बाद अतीव प्रसन्नता के साथ उन्होंने गोप बालक श्रीकर को शिव जी की उपासना के सम्बन्ध में बताया।

पूजा-अर्चना की जो विधि और आचार-व्यवहार भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, उसे भी श्री हनुमान जी ने विस्तार से बताया। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे समस्त भूपालों तथा राजा चन्द्रसेन से और गोप बालक श्रीकर से विदा लेकर वहीं पर तत्काल अन्तर्धान हो गये। राजा चन्द्रसेन की आज्ञा प्राप्त कर सभी नरेश भी अपनी राजधानियों को वापस हो गये।

कहा जाता है भगवान महाकाल तब ही से उज्जयिनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं।

हर हर महादेव

मासिक दुर्गाष्टमी आज

वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार 01 अगस्त को सावन माह की दुर्गा अष्टमी है। यह पर्व हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत की देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर देवी मां दुर्गा की कृपा बरसती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर शुभ योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में देवी मां दुर्गा की पूजा एवं भक्ति करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही साधक के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। कहते हैं कि देवी मां दुर्गा अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं।

मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ मुहूर्त

==========

01 अगस्त को सुबह 04 बजकर 58 मिनट पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होगी और 02 अगस्त को सुबह 07 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी। देवी मां दुर्गा की पूजा निशा काल में होती है। इसके लिए 01 अगस्त के दिन सावन महीने की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी।

मासिक दुर्गा अष्टमी शुभ योग

==========

सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर शुभ योग का संयोग बन रहा है। शुभ योग का संयोग रात भर है। ज्योतिष शुभ योग को मंगलकारी मानते हैं। इस योग में शुभ काम कर सकते हैं। साथ ही शुभ योग में देवी मां दुर्गा की पूजा करने से सभी कामों में सफलता और शुभता प्राप्त होगी। इसके साथ ही सावन माह की दुर्गा अष्टमी पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। भद्रा योग शाम 06 बजकर 10 मिनट तक है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। इन योग में देवी मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान प्राप्त होगा।

दुर्गा अष्टमी का महत्व

==========

शास्त्रों में वर्णित है कि जो साधक सच्चे मन से अष्टमी व्रत रखते हैं और देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख-समृद्धि, शांति और उन्नति का वास होता है।

पूजा विधि

==========

* सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनें।
* घर या मंदिर में देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं।
* लाल फूल, लाल चूड़ी, सिंदूर, रोली, अक्षत और लाल फल अर्पित करें।
* दुर्गा सप्तशती का पाठ या मां दुर्गा के 108 नामों का जप करें।

*व्रत रखते हुए दिनभर मां दुर्गा का स्मरण करें और शाम को आरती करें।

विशेष फल की प्राप्ति

==========

कहा जाता है कि अष्टमी के दिन किए गए दान, पूजन और जप का फल सौगुना मिलता है। यदि आप जीवन में किसी विशेष संकट या रोग से परेशान हैं, तो इस दिन व्रत करके मां दुर्गा से प्रार्थना करें — आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।

शिवमय सावन : भक्ति, प्रकृति और चेतना का संगम

जब आकाश नील धवल वस्त्र धारण करता है, जब मेघों की वीणा पर इंद्रधनुषी सुर बजते हैं, तब धरती सावन के स्वर्णिम कणों से झूम उठती है। ऐसे ही अद्भुत ऋतु में, प्रकृति अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा से एक ही नाम का जाप करती है— देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव का। शिव और सावन का संबंध केवल धार्मिक नहीं, वह भावनाओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की चेतना का अद्वितीय संगम है।

सावन माह, जैसे प्रकृति का प्रेमपत्र हो, जिसे वह भगवान शंकर को अर्पित करती है। हर बूँद, हर फूल, हर वायु की सरसराहट जैसे शिव के नाम का संकीर्तन करती है। यह वह समय होता है जब गगन अपने नेत्रजल से शिव के मस्तक पर अभिषेक करता है और धरती अपने हरित आभूषण से उनके चरणों में समर्पण करती है।

शिव, जो स्वयं विरक्त योगी हैं, लेकिन सावन में प्रेम के प्रतीक बन जाते हैं। उनका गले में बसा नाग सावन की सर्पिल धाराओं

का प्रतीक है, उनका मस्तक पर बहता गंगा जल इस पावन ऋतु की पवित्रता को उद्घाटित करता है, और उनका त्रिनेत्र जैसे इस ऋतु में मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को जागृत करने वाला प्रकाश है।

सावन के सोमवार जैसे श्रद्धा की सुवर्ण मालाएं हों, जिनमें हर कण भक्तिभाव से झिलमिलाता है। व्रतधारी नारियाँ, कन्याएँ और गृहस्थजन जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों में तपते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वैसे ही शिव के चरणों में अपनी कामनाओं, पीड़ाओं और विश्वास का अर्पण करते हैं। शिव स्वयं 'विलक्षणता के प्रतीक' हैं—वह जो श्मशान में रमते हैं, लेकिन हृदयों में धड़कते हैं; जो संहारक हैं, परंतु कल्याणकारी भी हैं, जो योगी हैं, परंतु गृहस्थ भी। और सावन उस सौंदर्य का उपहार है जिसमें शिव का यह विराट स्वरूप और भी अधिक उज्ज्वल होकर प्रकट होता है। सावन में बेलपत्र जैसे शिव को समर्पित प्रकृति के प्रेमपत्र हैं, और धतूरा जैसे तप की कसौटी। हर मंदिर, हर शिवालय, हर गूंजता 'ॐ नमः शिवाय' शिव और सावन के इस दिव्य संबंध की गाथा को प्रतिध्वनित करता है, मानों, इस मास में, जैसे समय भी रुक कर शिव का ध्यान करता है, और कण-कण से उनकी उपासना लेती है। शिव और सावन, दो नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं—एक संवेदना, दूसरा उसकी अभिव्यक्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा उसकी पूजा। एक मौन है, दूसरा उसका संगीत। और जब दोनों मिलते हैं, तो सृष्टि शिवमय हो उठती है। यह ऋतु केवल वर्षा की ही नहीं, यह शिव की आराधना की भी ऋतु है- भाव की, भक्ति की, और परब्रह्म के साथ एकत्व की।

डॉ. पंकज भारती - सारण, बिहार।

यह सच की ताकत है कि झूठ बोलने वाले को भी सच ही पसंद होता है। जो हमारी भावनाओं को समझ कर भी हमें तकलीफ देता हो, वो कभी हमारा अपना नहीं हो सकता।

मन की सच्चाई/अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते है जब हम दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं। विनम्रता/सहनशीलता ही मानव जीवन का सबसे बड़ा सामर्थ्य है। ध्यान रहे कि सामर्थ्य का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों को कितना झुका सकते है अपितु यह है कि हम स्वयं कितने संवेदनशील हैं। समझ/सामर्थ्य आते ही व्यक्ति के भीतर सम्मान का भाव भी जागृत हो जाता है। सदैव इस बात के लिए प्रयासरत रहें कि हम सम्मान पाने की लालसा रखने वाले नहीं, सम्मान देने वाले बन सकें। हमारे बल का प्रयोग किसी को गिराने के लिए नहीं, अपितु सबके/दूसरों के सम्मान की रक्षा हेतु हो। भला ऐसा सामर्थ्य किस काम का, जो हमारी नम्रता का हरण एवं हमारे अहंकार को पुष्ट करता हो। वास्तव में जिस के पास धैर्य है वो इंसान जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है।

वात पित्त कफ के दोष तीनों को संतुलित करे इस आयुर्वेदिक उपाय से...अंत तक अवश्य पढ़े

वात पित्त और कफ के दोषः-

पोस्ट को धयान से 2 बार पढ़े

शरीर 3 दोषों से भरा है

#वात(GAS) -लगभग 80 रोग

#पित्त(ACIDITY)- लगभग 40 रोग

#कफ(COUGH) -लगभग 28 रोग

यहाँ केवल त्रिदोषों के मुख्य लक्षण बतये जायेगे और वह रोग घरेलू चिकित्सा से आसानी से ठीक होते है

सभी परहेज विधिवत रहेंगे जैसे बताता हूँ

जिस मनुष्य की बड़ी आंत में कचड़ा होता है बीमार भी केवल वही होता है

एनीमा एक ऐसी पद्धति है जो बड़ी आंत को साफ करती है और किसी भी रोग को ठीक करती है

संसार के सभी रोगों का कारण इन तीन दोष के बिगड़ने से होता है

वात(#GAS) अर्थात वायुः-

--शरीर मे वायु जहां भी रुककर टकराती है, दर्द पैदा करती है, दर्द हो तो समझ लो वायु रुकी है

--पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, घुटनो का दर्द ,सीने का दर्द आदि

--डकार आना भी वायु दोष है

--चक्कर आना, घबराहट और हिचकी आना भी इसका लक्षण है

कारणः-

oooooooo

--गैस उत्तपन्न करने वाला भोजन जैसे कोई भी दाल आदि गैस और यूरिक एसिड बनाती ही है

--यूरिक एसिड जहाँ भी रुकता है उन हड्डियों का तरल कम होता जाता है हड्डियाँ घिसना शुरू हो जाती है ,उनमे आवाज आने लगती है, उसे डॉक्टर कहते है कि ग्रीस समाप्त हो गई, या फिर स्लिप डिस्क या फिर स्पोंडलाइटिस, या फिर सर्वाइकल आदि

--प्रोटीन की आवश्यकता सिर्फ सेल्स की मरम्मत के लिए है जो अंकुरित अनाज और सूखे मेवे कर देते है

--मैदा और बिना चोकर का आटा खांना

--बेसन की वस्तुओं का सेवन करना

--दूध और इससे बनी वस्तुओं का सेवन करना

-आंतो की कमजोरी इसका कारण व्यायाम न करना

निवारणः-

ooooooooo

--अदरक का सेवन करें, यह वायु समाप्त करता है, रक्त पतला करता है कफ भी बाहर निकालता है, सोंठ को लेकर रात में गुनगने पानी से आधा चम्मच खायें।

--लहसुन किसी भी गैस को बाहर निकालता है,

यदि सीने में दर्द होने लगे तो तुरन्त 8-10 कली लहसुन खा ले, ब्लॉकेज में तुरंत आराम मिलता है

--लहसुन कफ के रोग और टीबी के रोग भी मारता है

--सर्दी में 2-2 कली सुबह शाम, और गर्मी में 1-1 कली सुबह शाम ले, और अकेला न खायें सब्जी या फिर जूस , चटनी आदि में कच्चा काटकर डालकर ही खायें

--मेथीदाना भी अदरक लहसुन की तरह ही कार्य करता है

प्राकृतिक उपचारः-

oooooooooooooo

गर्म ठंडे कपड़े से सिकाई करे, अब उस अंग को पहले छुएं यदि वो गर्म है तो ठंडे सिकाई करे और वह अंग अगर ठंडा है तो गर्म सिकाई करे और अगर न गर्म है और न ठंडा तो गर्म ठंडी सिकाई करे एक मिनट गर्म एक मिनट ठंडा

कफ(#COUGH):-

--मुँह नाक से आने वाला बलगम इसका मुख्य लक्षण है

--सर्दी जुखाम खाँसी टीबी प्लूरिसी

निमोनिया आदि इसके मुख्य लक्षण है

--सांस लेने में तकलीफ अस्थमा आदि या सीढी चढ़ने में हाँफना

कारणः-

oooooooo

--तेल एव चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन

--दूध और इससे बना कोई भी पदार्थ

--ठंडा पानी और फ्रिज की वस्तुये खाना

--धूल ,धुएँ आदि में अधिक समय रहना

--धूप का सेवन न करना

निवारणः-

oooooooo

--विटामिन C का सेवन करे यह कफ का दुश्मन है यह संडास के रास्ते कफ निकालता है, जैसे आवंला

--लहसुन, यह पसीने के रूप में कफ को गलाकर निकालता है

--Bp सामान्य हॉगा

--ब्लड सर्कुलेशन ठीक हॉगा

--नींद अच्छी आएगी

--अदरक भी सर्वश्रेष्ठ कफ नाशक है

प्राकृतिक उपचार

oooooooooooo

--एक गिलास गुनगने पानी मे एक चम्मच नमक डालकर उससे गरारे करे

--गुनगने पानी मे पैर डालकर बैठे, 2 गिलास सादा ।पानी पिये और सिरर पर ठंडा कपड़ा रखे, रोज 10 मिनट करे

--रोज 30-60 मिनट धूप ले

पित्त(#ACIDITY):-पेट के रोग

--वात दोष और कफ दोष में जितने भी रोग है उनको हटाकर शेष सभी रोग पित्त के रोग है, BP, शुगर, मोटापा, अर्थराइटिस, आदि

--शरीर मे कही भी जलन हो जैसे पेट मे जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन ,मल त्याग करने में जलन, शरीर की त्वचा में कही भी जलन,

--खट्टी डकारें आना

--शरीर मे भारीपन रहना

कारणः-

oooooo

--गर्म मसाले, लाल मिर्च, नमक, चीनी, अचार

--चाय ,काफी,सिगरेट, तम्बाकू, शराब,

--मांस ,मछली ,अंडा

--दिनभर में सदैव पका भोजन करना

--क्रोध, चिंता, गुस्सा, तनाव

--दवाइयों का सेवन

--मल त्याग रोकना

--सभी 13 वेग को रोकना जैसे छींक, पाद, आदि

निवारण

ooooooo

--फटे हुए दूध का पानी पिये, गर्म दूध में नीम्बू डालकर दूध को फाड़े, वह पानी छानकर पिए, पेट का सभी रोग में रामबाण है, सभी प्रकार का बुखार भी दूर करता है

--फलो व सब्जियों का रस, जैसे अनार का रस, लौकी का रस, पत्ता गोभी का रस आदि

--निम्बू पानी का सेवन

प्राकृतिक उपचार

oooooooooooo

--पेट को गीले कपड़े से ठंडक दे

--रीढ़ की हड्डी को ठंडक देना, लकवा इसी रीढ़ की हड्डी की गर्मी से होता है, गीले कपड़े से रीढ़ की हड्डी पर पट्टी रखें

--व्यायाम ,योग करे

--गहरी नींद ले

कौन हैं एसबीके सिंह? जिन्हें मिली दिल्ली पुलिस की कमान

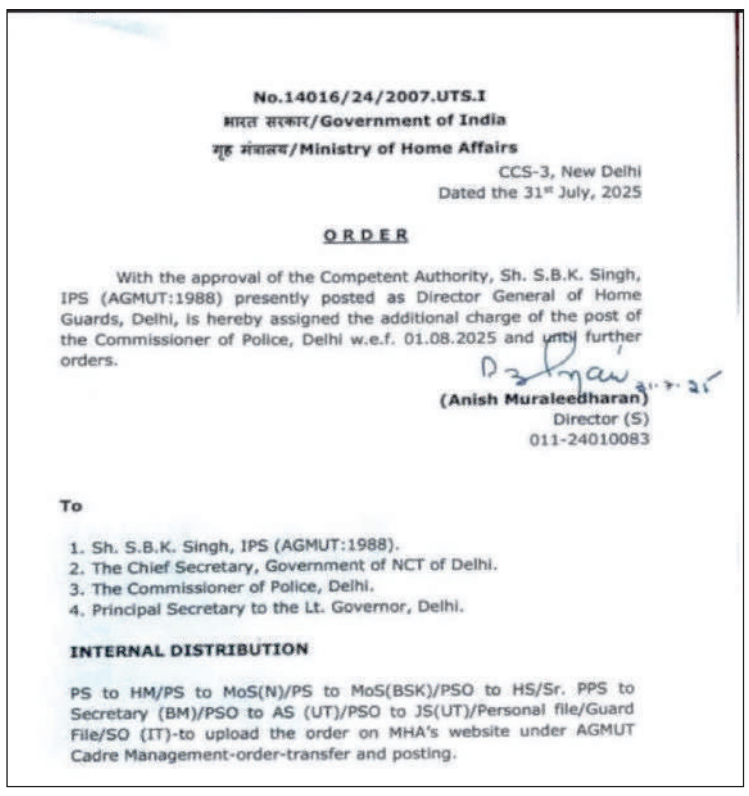

No.14016/24/2007.UTS.I
भारत सरकार/Government of India
गृह मंत्रालय/Ministry of Home Affairs

CCS-3, New Delhi
Dated the 31st July, 2025

ORDER

With the approval of the Competent Authority, Sh. S.B.K. Singh, IPS (AGMUT:1988) presently posted as Director General of Home Guards, Delhi, is hereby assigned the additional charge of the post of the Commissioner of Police, Delhi w.e.f. 01.08.2025 and until further orders.

(Anish Muraleedharan)
Director (S)
011-24010083

To

1. Sh. S.B.K. Singh, IPS (AGMUT:1988).
2. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi.
3. The Commissioner of Police, Delhi.
4. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.

INTERNAL DISTRIBUTION

PS to HM/PS to MoS(N)/PS to MoS(BSK)/PSO to HS/Sr. PPS to Secretary (BM)/PSO to AS (UT)/PSO to JS(UT)/Personal file/Guard File/SO (IT)-to upload the order on MHA's website under AGMUT Cadre Management-order-transfer and posting.

दिल्ली होम गार्ड के डीजी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनकी सेवानिवृत्ति में केवल पांच महीने बचे हैं और इस दौरान वे दोनों पदों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। यह नियुक्ति उनके कार्यकाल के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे विस्तार से पढ़िए।

नई दिल्ली। दिल्ली होम गार्ड के डीजी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस आयुक्त का एडिशनल चार्ज दिया गया है। इनकी सेवा निवृति का समय पांच महीने बचा है। वहीं, माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय आगे इन्हें फूल फ्लेस चार्ज देकर एक या दो साल का सेवा विस्तार भी दे सकता है। चार साल बाद यूटी कैडर के आइपीएस को फिर से आयुक्त बनाया गया है।

कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे एसबीके सिंह

एस. बी. के. सिंह बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। एसबी के सिंह आज चार बजे पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे।

संजय अरोड़ा आज हो गए सेवानिवृत्त

बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा आज (गुरुवार) 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। इसके साथ ही नए आयुक्त को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है।

पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन आखिरकार पुलिस विभाग ने उनका फेयरवेल सेरेमोनियल परेड आयोजित करने की घोषणा कर दी है।

न्यू पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में हुआ विदाई समारोह

संजय अरोड़ा का विदाई समारोह 31 जुलाई को किंग्सवे कैंप के न्यू पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में हुआ, जिसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को निमंत्रण भेजा गया था। उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में सेवा विस्तार को लेकर अफवाहें तैर रही थीं, हालांकि आधिकारिक स्तर पर अब साफ गया है कि वे रिटायर हो गए हैं। संजय अरोड़ा के पुलिस आयुक्त रहते दिल्ली पुलिस ने कई अहम मामलों व कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।

दिल्ली में धूल से निपटने के लिए प्रमुख रास्तों पर लगाए जाएंगे मिस्ट स्प्रेयर, प्रदूषण से मिलेगी लोगों को राहत

दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण से निपटने के लिए कनाट प्लेस और खान मार्केट जैसे प्रमुख स्थानों पर मिस्ट स्प्रेयर लगाएगी। 19 करोड़ रुपये की इस परियोजना में 24 सड़कें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र शामिल हैं। पहले चरण में बाराखंभा रोड जैसी 10 सड़कें शामिल हैं। दूसरे चरण में शाहजहां रोड जैसी 14 सड़कें शामिल हैं। हनुमान मंदिर और कनॉट प्लेस जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मिस्ट फागिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे।

नई दिल्ली। राजधानी के कई प्रमुख स्थानों, जिनमें कनॉट प्लेस और खान मार्केट भी शामिल हैं, धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार चरणबद्ध परियोजना के तहत जल्द बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रेयर लगाएगी।

24 सड़कों और अनेक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों को कवर करते हुए, इस पहल पर 19 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी और इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा।

पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के तहत बाराखंभा रोड, फिरोजशाह रोड, सिकंदरा रोड और भगवान दास रोड सहित 10 प्रमुख सड़कों पर मिस्टिंग सिस्टम लगाने की योजना है।

इस चरण में 7.97 करोड़ रुपये की लागत से 15,330 नोजल वाले 511 खंभे लगाए जाएंगे। मंदिर मार्ग, तिलक मार्ग और सुब्रमण्यम भारती मार्ग जैसी सड़कें पहले चरण की सबसे लंबी सड़कों में से हैं।

मंदिर मार्ग, जो 1,790 मीटर लंबा है, पर 114 पोल और 3,420 नोजल लगाए जाएंगे। तिलक मार्ग, जो 1,230 मीटर लंबा है, पर 61 पोल और 1,830 नोजल लगाए जाएंगे जबकि सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जो 2,210 मीटर लंबा है, पर 67 पोल और 2,010 नोजल लगाए जाएंगे।

परियोजना के दूसरे चरण में शाहजहां रोड, अरबिंदो मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट और अशोक रोड सहित 14 अतिरिक्त सड़कें शामिल होंगी। इस चरण में एमसीडी 7.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 530 पोल और 15,300 से ज्यादा नोजल लगाएगी।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश द्वारा व्यापारी एवम उधमी सम्मेलन में वोकल फार लोकल शपथ कार्यक्रम का आयोजन

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। उद्योग भवन दिल्ली में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश द्वारा व्यापारी एवम उधमी सम्मेलन में वोकल फार लोकल शपथ कार्यक्रम जिसका आयोजन 1 अगस्त को होटल ला, मंगोलपुरी में किया जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि सुनील सिंघी (चेयरमैन - राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सभी व्यापारी बंधुओं को शपथ दिलवाएंगे।

आज दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों ने सुनील सिंघवी को आमंत्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनसे व्यापारियों से सम्बन्धित कई विषयों पर चर्चा भी हुई एवं भविष्य की कई योजनाओं पर भी चर्चा हुई।

प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय चेयरमैन बाल किशन अग्रवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीश बेरीवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामगोपाल गोयल, उपाध्यक्ष जगदीश मोदी, दिल्ली प्रदेश प्रधान नवीन गर्ग, वरिष्ठ महामंत्री मुनीष बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव मित्तल, कोषाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, उपाध्यक्ष गिरीश मित्तल, महावीर गोयल, विपिन अग्रवाल सम्मिलित हुए।

आने वाले पांच सालों में दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में कई स्तरों पर आमूल चूल परिवर्तन कर देगी-- शिक्षा मंत्री

मुख्य संवाददाता

दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली में रोहिणी स्थित सर्वोदय विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित व्यावसायिक प्लेसमेंट ड्राइव, रोजगार मेला-2025- 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री राजकुमार चौहान शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक और बच्चों को रोजगार प्रदान करने वाली कई कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने रोजगार देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की कि वह किस प्रकार से सरकारी स्कूलों के बच्चों का चयन अपनी कंपनियों में रोजगार देने के लिए करते हैं और उनको कितना वेतन और सुविधा आदि दी जाएंगी। इसके साथ-साथ उन्होंने बच्चों से भी संवाद किया कि कैसे वह इन कंपनियों के साथ मिलकर अपना भविष्य सवारेंगे और समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ेंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक प्लेसमेंट ड्राइव नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा ने कितनी प्रगति की है और दिल्ली सरकार आने वाले समय में किस तरह से हर छात्र को सम्मानजनक और संभावनाओं से भरा भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के

अनुरूप है, जो शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर बल देती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक छात्र न केवल विद्यालय के लिए तैयार हो, बल्कि कौशलयुक्त शिक्षा और भविष्य की चुनौतियां के लिए भी तैयार हो।

सूद ने कहा, यह ड्राइव छात्रों के लिए उद्योग जगत से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे न केवल करियर के विकल्प समझते हैं, बल्कि व्यावसायिक दुनिया की अपेक्षाओं से भी रूबरू होते हैं। उन्होंने आगे कहा की पिछले 11 सालों में एक परिवर्तन देश में आना प्रारंभ हुआ है। लीगेसी और एंटाइटलमेंट के स्थान पर अब योग्यता के अनुसार उपयुक्त अवसर युवाओं को मिलने लगे हैं, जिससे हुनर और प्रतिभा को पहचान मिलने लगी है, जिसके कारण अनेक साधारण घरों के बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर चयनित हो रहे है।

सूद ने कहा की हुनर और प्रतिभा को अवसर मिलने का जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है, वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कृत संकल्प हैं।

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा की प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी योजना के पहल से रोजगारपरक अनेक ऐसे अवसर शुरू हुए हैं जिसमें आत्मविश्वास से लबरेज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्थान पर, अपने ज्ञान पर भरोसा करने वाले युवाओं को रोजगार के कई अवसर मिलने का रास्ता खुला है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षा विभाग इसे सामूहिक ज़िम्मेदारी समझता है कि कोई चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय का हो उन सबको कौशल निर्माण और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से समान मंच, समान अवसर मिलना ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है हमारी काम करने की शैली है।

दिल्ली के हरेक स्कूल में आने वाले पाँच साल में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के विद्यार्थी के लिए हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, आईसीटी लैब, निजी कंप्यूटर दिल्ली सरकार तेजी से उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने उपस्थित छात्रों से कहा की जब आप इन सरकारी स्कूलों से बारहवीं पास करके यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहां के गैजेट से, वहां की टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं होंगे। क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के साथ आपको

प्रैक्टिकल करने के अवसर भी प्रदान किये जाएंगे। किसी बच्चे को ऐसा नही लगेगा की स्कूलों में सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता है बल्कि इन स्कूलों में स्किल वेसड शिक्षा भी दी जा रही है।

सूद ने कहा की यहां पर जो बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे एचसीएल, हल्दीराम, टेक महिंद्रा आदि बच्चों के प्लेसमेंट के लिए आई है और यहां पर आकर उन्होंने युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का काम किया है। यह हमारे सरकारी स्कूलों, शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रशासकों, हमारी शिक्षिकाओं का और स्कूल के प्रशासन का साझा प्रयास है कि ऐसे बड़े-बड़े नियोजक यानी एंप्लॉयर्स आप लोगों की प्रतिभा को पहचानने के लिए आपके स्कूलों में आ रहे हैं।

ये अवसर आपको उन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करने का इंडस्ट्री के साथ सीखने का मौका देता है। और आज के इस रोजगार मेले के आयोजन की सफलता इस बात की प्रतीक है की हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चें अब नौकरी नहीं ढूंढेंगे बल्कि नौकरियां हमारे बच्चों को ढूंढेगी।

'इशानी' की अनोखी दास्तान लेकर आया स्टार प्लस, प्रोमो हुआ आउट

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। स्टार प्लस लेकर आया है अपना नया फिक्शन शो 'इशानी', जो एक युवा लड़की की अपने सपनों और पहचान को वापस पाने की जंग की कहानी है, उस दुनिया में जो उसे सीमाओं में बांधना चाहती है। यह शो दर्शकों के लिए एक नया और भावनात्मक किस्सा लेकर आ रहा है, जिसमें एक ऐसी महिला लीड है जिससे लोग आसानी से जुड़ सकेंगे, जो हिम्मत के साथ समाज की बेड़ियों को तोड़ने का साहस रखती है। 'इशानी' सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनकही लड़ाइयों की भी आवाज़ है, जिन्हें कई महिलाएं शादी के बाद अपने सपनों को छोड़ देने की मजबूरी में लड़ती हैं।

प्रोमो की शुरुआत इशानी के दमदार मोनोलॉग से होती है, जहां वह खुद को एक ऐसे पंछी से जोड़ती है जो आसमान का है, पिंजरे का नहीं। शादीशुदा होने और नियमों से बंधे होने के बावजूद उसका हौसला टूटा नहीं है। उसका पति चाहता है कि वह अपने आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने को भूलकर सिर्फ घर और बच्चों की देखभाल करे। इशानी को कॉलेज जाने की इजाज़त है, लेकिन सख्त शर्त के साथ ओर वो है किसी से बात नहीं करनी।

कहानी में मोड़ तब आता है जब इशानी क्लास में पहुंचती है और पता चलता है कि उसके प्रोफेसर अनुराग हैं — उसका पुराना प्यार। अनुराग उससे सवाल करता है कि उसने उसका इंतज़ार क्यों नहीं किया, जिससे उनके अतीत की वो भावनाएं और फैसले झलकते हैं, जिन्होंने दोनों को अलग कर दिया। प्रोमो में इशानी के दिल और दिमाग में चल रहे तूफान को बखूबी दिखाया गया है, जहां वह अपने निजी सपनों और उस पर थोपे गए फ़र्ज़ों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। प्रोमो में निजी दर्द और चुपचाप सहने की ताकत को खूबसूरती से जोड़ा गया है, जो एक ऐसी कहानी की शुरुआत करता है जिसमें टकराव, दबे हुए जज़्बात और फिर से उठ खड़े होने की जलती हुई चाहत साफ झलकती है। देखिए 'इशानी', इस मंगलवार से शाम 7:20 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर।

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पेट स्कैन सुविधा शुरू, प्राइवेट लैब में महंगी जांच से मरीजों को राहत

सफदरजंग अस्पताल में पेट-सीटी स्कैन मशीन लगने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एम्स के बाद यह दूसरा सरकारी अस्पताल है जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से लाइसेंस मिलने के बाद ट्रायल शुरू हो गया है और जल्द ही नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एक और मशीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है जिससे मरीजों को किफायती दर पर जांच मिल सकेगी।

नई दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में एक पेट (पाजिट्रान एमिशन टोमोग्राफी)-सीटी स्कैन मशीन लग गई है। एम्स के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह दूसरा अस्पताल है, जहां पेट-स्कैन मशीन लगा गई है।

इसके संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) से लाइसेंस मिलने के बाद इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जल्द ही इस मशीन से कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सफदरजंग अस्पताल में पेट स्कैन की सुविधा मिलने लगेगी।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक अन्य पेट स्कैन मशीन के खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। यह मशीन भी अस्पताल में जल्द लग जाएगी। इससे कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

यह मशीन महंगी होने के कारण सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में पेट-स्कैन जांच की सुविधाएं समिति है। दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के पांच अस्पतालों पेट-स्कैन मशीन उपलब्ध है।

जिसमें एम्स, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान, आइएलबीएस, आर्मी अस्पताल और इनमास (इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज) शामिल है। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में न्यूक्लियर मेडिसिन के डाक्टर नहीं होने से मशीन बंद पड़ी है।

आर्मी अस्पताल में सामान्य मरीजों के इलाज के लिए नहीं जा सकते। वहीं आईएलबीएस में भी जांच का शुल्क बहुत महंगा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में किफायती पेट-स्कैन जांच का विकल्प एम्स व इनमास में ही उपलब्ध है।

निजी लैबों में शरीर के पूरे हिस्से के पेट-स्कैन जांच का शुल्क 16,000-24,000 रुपये है। इस वजह से सफदरजंग अस्पताल में लंबे समय से पेट-स्कैन मशीन लगाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस अस्पताल में किफायती शुल्क पर मरीजों को जांच की सुविधा मिल सकेगी।

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ट्रायल के रूप में 40 मरीजों की जांच हो चुकी है। जांच का शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही जांच का शुल्क निर्धारित कर पेट-स्कैन जांच की नियमित सेवा शुरू की जाएगी।

सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह भंडारी ग्राम प्रधान सेवक चुने गए

स्वतंत्र सिंह भुल्लर। सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अन्नपूर्णा रोटी बैंक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश भंडारी जी उत्तराखंड के सेरा मालकोटी ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान सेवक चुनेगए हैं क्षेत्र में खुशियों की लहर दौड़ उठी पूर्व में दिल्ली से राजेश सिंह भंडारी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा में रहे हैं लेकिन आज अपनी जन्म भूमि मिट्टी की ओर लौट कर गए और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा पहली बारी में सफलता हासिल हुई राजेश सिंह भंडारी को समाज से ज्यादा लगाओ रहता था अन्नपूर्णा रोटी बैंक के अध्यक्ष थे दिल्ली के प्रत्येक इलाकों में इनकी अच्छी खासी छवि बनी हुई थी पिछले कई वर्षों से अपने जन्म भूमि उत्तराखंड में सामाजिक सेवा में सक्रिय हुए पहली बारी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े भारी बहुमत से सफलता मिली है।

डीएनटी का राष्ट्रीय सम्मेलन लोक कला मंच लोधी कॉलोनी में सम्पन्न

नई दिल्ली। डीएनटी का राष्ट्रीय सम्मेलन लोक कला मंच लोधी कॉलोनी में 30 जुलाई को आयोजित किया गया, जिसमें कई राज्यों के गणमान्य लोगों ने सैकड़ो की संख्या में उपस्थिति होकर वंचित समाज की समस्याओं और उसके समाधान पर चिंतन मंथन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण उपस्थित रहे। इसके अलावा डॉक्टर ऋषि भटनागर चेयरमैन आईटी future tech, भरत भाई पटनी सदस्य DWBDNC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, प्रवीण गुधे सदस्य DWBDNC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कुलदीप जी, भाजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन MCD धर्मवीर सिंह आदि के साथ DNT समाज की समस्याओं और उसके निदान पर गहन चिंतन मंथन किया। इदाते कमिशन की रिपोर्ट को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा तुरंत लागू करने की मांग पूरी गंभीरता से उठाई गई। इस सम्मेलन में यह मांग की गई कि SC/ST आयोग की तरह DNT commission बनाया जाए। इदाते कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे DNT समाज का सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। केंद्र सरकार को इदाते कमीशन की रिपोर्ट को अक्षरशः लागू करना चाहिए। DNT समाज आज भी राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ है तथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर है। इदाते कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से ही DNT समाज का भला हो सकता है।

भगवान पारसनाथ को अर्पित हुआ 23 किलो का निर्वाण लाडू, श्रद्धा और भक्ति का भव्य उत्सव, निर्मल सदन में हुआ दिव्य आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की भव्य कृत्रिम रचना के दर्शन और भगवान पारसनाथ की अनूठी पालकी यात्रा का दिव्य आयोजन निर्मल सदन में संपन्न हुआ। आयोजन की शुरुआत श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, छिपी टोला से हुई, जहां भगवान पारसनाथ को बैंड-बाजों के साथ सुसज्जित पालकी में विराजमान कर भक्ति भाव से निर्मल सदन तक लाया गया।

निर्मल सदन पहुंचने पर भगवान पारसनाथ का विधिवत अभिषेक और शांतिधारा मुनिश्री सौम्यदत्त सागर महाराज के पावन सान्निध्य में संपन्न हुई। इसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा सुसज्जित थाल में अस्त्र द्रव्य समर्पित कर भगवान की पूजन-अर्चना की गई तथा श्रद्धा भाव से निर्वाण कांड का पाठ किया गया।

इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान पारसनाथ को 23 किलो का विशाल निर्वाण लाडू अर्पित किया, जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बना। भक्ति, आस्था और परंपरा से ओतप्रोत यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बन गया और समस्त वातावरण भक्तिरस से सराबोर हो उठा।

मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने इस अवसर पर कहा, श्रावण मास को भारतीय संस्कृति में संकटों के निवारण का मास माना गया है। यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। हमारी संस्कृति में दो प्रमुख परंपराएं

हैं - वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। श्रमण वह है जो तप, त्याग और आत्मसंयम का मार्ग अपनाता है। हमें लगता है कि आज जिस वक्त ने भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति की वह दुनिया का अद्भुत भक्त है। आज का दिन उस अनुपम भक्ति का साक्षी बना, जो भगवान पार्श्वनाथ के प्रति जनमानस में विद्यमान है।

इस दिव्य आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार जैन, मुरारीलाल जैन, अनिल फौजी, प्रवेश जैन, अक्षय जैन, पन्नालाल बेनाडा, अशोक जैन, राजेश जैन, हजारीलाल जैन, दयाचंद जैन, प्रताप जैन, विमल जैन, संजीव जैन, मुन्नालाल जैन, रविंद्र जैन, दीपक जैन, मोहित जैन, चंद्रमोहन जैन सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समुचित समन्वय मीडिया प्रभारी दिलीप जैन साहब द्वारा किया गया।

नगला कारे में दलित परिवारों को राहत, मकान तोड़े जाने के आदेश निरस्त, सांसद चाहर व भाजपा नेता उपेंद्र सिंह के प्रयासों से मिला न्याय

परिवहन विशेष न्यूज

आगराः-धनौली के मजरा नगला कारे में निवास कर रहे 100 से अधिक दलित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन द्वारा उनके मकान तोड़े जाने के जारी आदेश को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ने निरस्त कर दिया है। यह निर्णय फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर के सक्रिय हस्तक्षेप और जनहित में किए गए प्रयासों का प्रतिफल माना जा रहा है।

सांसद चाहर ओर भाजपा नेता उपेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ़ता से पैरवी की। इस निर्णय के पश्चात भाजपा नेता एवं अनुसूचित जाति आयोग के पूर्वप्रदेश कोऑर्डिनेटर उपेंद्र सिंह ने प्रधान व ग्रामीणों के साथ सांसद श्री चाहर से दिल्ली स्थित आवास पर भेंट की। भाजपा नेता उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में लोकेश प्रधान, डॉ. ब्रजेश बघेल, तेज कपूर, राकेश सोनी आदि ने सांसद का पट्टिका पहनाकर स्वागत किया और उनके प्रयासों के लिए आभार प्रकट किया। स्थानीय लोगों और दलित समाज ने सांसद के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे जनता की जीत बताया।

मेरे एहसास

तुम पर न जाने कितनी कविताएँ लिखती हूं
मेरी पहचान बन गए हो तुम
मेरी कविताएँ तुम्हारे प्रेम, इंतज़ार, विरह, यादें
हर एहसास को दर्शाती हैं
तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की खुबसूरत यादें
तुम बिन हृदय की वेदना, बेचैनियां समाहित हैं
इन कविताओं के हर अल्फाजों में
तुम्हारी कहीं बातें मेरे हृदय और मन मस्तिष्क में
गहरे छाप छोड़ जाते हैं
तुम्हें एक झलक देख पाने की
आस लिए इंतजार करती आंखें
तुम्हारी आवाज सुन पाने को बैचेन मन
कितना वो पल सुकून भरा होता है
जिन पलों में संग तुम होते हो
तुम्हारे संग न होकर भी
तुम्हारी बेइंतहा फिक्र,
परवाह करता ये मन
तुम्हारी एक आवाज
से भी तसल्ली कर
लेता हैं।

तृषा सिंह मोकामा, पटना

मां मैं वापस आऊंगा

मां तु मन में धीरज रख
मेरी उम्मीद के हौसले परख
दुनिया को छोड़ ,
मुझ पर भरोसा कर।
गमगीन हाल से निकल ,
गहरे अवसाद से उभर।।
तूने अपने हाथों से ,
जो टिफिन मुझे दिया था।
तेरी चूड़ियां सहलाते हुए ,
मैंने हाथों में लिया था।।
तू दौड़ कर मेरे लिए ,
पानी भर लाई थी।
मेरा भारी भरकम झोला,
खुद ही उठा आई थी।।
जाते-जाते जब मैंने,
पापा से बाय-बाय किया था।
उनकी मंद मुस्कान ने,
मन मोह लिया था।।
वो पल हर मन को
बेहद भाया होगा ।
क्या मालूम था स्कूल में
यमराज आया होगा।।
मां तेरी सब आशाएं
पूरी हो जाती।
काश मेरा साथ
मेरी सांसे दे जाती।।
मां तेरे दूध का
मुझ पे कर्ज़ बाकी है।
लाल हूं मैं तेरा
मेरे भी फर्ज बाकी है।।
सारे सपने सच कर दूंगा।
हां मैं फिर से जनम लूंगा।।
यह सौभाग्य फिर से
तुझे ही मिलेगा ।
तेरी ममता की छाया में
फिर से बचपन पलेगा।।
सत्ताधिशो से आज
जनमत यही कहेगा।
जर्जर स्कूलों में अब
कोई बच्चा ना रहेगा ।।
मौत के तांडव पर
पसरा हुआ सन्नाटा है।
खोखली अव्यवस्थाओं पर
यह तमतमाता चांटा है।।
क्या चंद सिक्कों की खनक से
वो खुशियां दे पाओगे।
मां की पुकार पे दौड़ते
बच्चे कहां से लाओगे।।

रचनाकार
दिनेश बारोठ दिनेश
शीतला कॉलोनी सरवन

यशोगोपाल रिसॉर्ट्स में हुआ नवनिर्मित फ्रंट ऑफिस का शुभारंभ

भक्ति और आध्यात्मिक परपंरा का संवर्धन कर रहा है अवध ग्रुप : महंत जयराम दास महाराज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रमणरेती क्षेत्र स्थित अवध गोविन्द विहार में संचालित होटल यशोगोपाल रिसॉर्ट्स में अवध ग्रुप वृंदावन द्वारा नवनिर्मित फ्रंट ऑफिस का शुभारंभ समारोह बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ आध्यात्मिक वातावरण में सम्पन्न हुआ।

फ्रंट ऑफिस का शुभारंभ करते हुए महंत जयराम दास महाराज ने कहा कि ब्रज के रासबिहारी परिकर की निधि पद्मश्री स्वामी हरगोविंद महाराज की प्रेरणा से उनके परिवारीजन ब्रज की संस्कृति, भक्ति और आध्यात्मिक परपंरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे है। देश-विदेश से ब्रज मंडल के दर्शनार्थ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को ब्रज का भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए यशोगोपाल रिसॉर्ट्स में हर संभव प्रयास किया जा रहा है जो कि अत्यन्त सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है।

अवध ग्रुप के संरक्षक स्वामी अवधेश शर्मा ने बताया कि अवध ग्रुप भगवान श्रीकृष्ण की पावन क्रीड़ास्थली वृन्दावन की पवित्र धरा पर होटल यशोगोपाल रिसॉर्ट्स में इस नवीन सुविधा के माध्यम से यात्रियों एवं भक्तों को और अधिक सुविधाजनक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।

इस अवसर पर डायरेक्टर अवध अनुज गोविन्द, मीरा शर्मा, प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, सृष्टि गोविन्द, श्वेता गोस्वामी, नीतू शर्मा, पार्षद राधाकृष्ण पाठक, संत नागेंद्र महाराज, जॉनी भाटिया, मनोज भाटिया, अवधेश गौतम, डॉ. राधाकांत शर्मा, आराध्य गोस्वामी, कृष्ण गोपाल बघेल, शिवदत्त मिश्रा, ब्रजबिहारी पांडे, जयवर्धन सिंह, अनुज यादव, अनिल सिंह, पवन कुमार आदि की उपस्थिति विशेष रही।

सोने के समय हर्ट अटैक आने के कारण जाने विस्तार से

डॉ हृदयेश कुमार

बल्लबगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

तिरखा कॉलोनी शिव मंदिर परिसर में अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही स्वास्थ्य भारत जैसे अन्य संकल्पों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हमेशा ही अपने जीवन के साथ सामाजिक सेवाओं पर निरंतर विकास कार्यों में समर्पित रहते हैं इस पर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहता है। थक-हारकर जब वे घर आते हैं तो उन्हें सोने का मन करता है। लेकनि सोने से भी कई खतरा रहता है। नींद के दौरान दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नींद में शरीर रेस्ट मोड में चला जाता है जिससे हार्ट रेट धीमी हो जाती है।

दिल हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है।

ये हमारे पूरे शरीर में खून पंप करता है।

इन दिनों दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता है। दिनभर की बिजी शेड्यूल के बाद जब इंसान थका हारा घर आता है तो उसे बिस्तर के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। कहते हैं कि शरीर को आराम देने के लिए सोना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल (heart) के लिए ये वक्त कभी-कभी सबसे ज्यादा खतरों से भरा भी हो सकता है?

खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो। अक्सर आपने सुना होगा कि सामने वाले को सोते-सोते हार्ट अटैक आया और तुरंत उस व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि नींद के दौरान दिल से जुड़ी समस्याओं, खासकर हार्ट फेलियर जैसी स्थिति का खतरा बढ़ जाता है और इसकी वजहें कई हैं। जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर एक्टिव मोड (sympathetic) से रेस्ट मोड (parasympathetic) में चला जाता है। ये बदलाव सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी है, उनके लिए ये कंडीशन धीमी हार्ट रेट (bradycardia), लो ब्लड प्रेशर, और अनियमित सांस की वजह बन सकती है। खासतौर पर ऐसा तब होता है जब इंसान गहरी नींद यानी REM sleep में होता है।

स्लीप एपनिया से बढ़ता है खतरा

उन्होंने बताया कि स्लीप एपनिया भी एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें व्यक्ति की नींद के दौरान सांस बार-बार रुकने लगती है। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। जिससे अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे दिल पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे दिल की कमजोरी या हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समस्या कई बार बिना पता चले बनी रहती है।

इसके अलावा जब कोई व्यक्ति लेटता है, खासकर अगर उसका दिल पहले से सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो पैरों में जमा हुआ फ्लूइड शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ खिसकने लगता है। इससे लंग्स में Fluid भरने, सांस फूलना और दिल पर दबाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से बहुत से हार्ट फेलियर पेशेंट्स को रात में नींद टूटने या अचानक सांस फूलने की शिकायत होती है। इसे मेडिकल भाषा में Paroxysmal Nocturnal Dyspnea कहा जाता है।

स्लीप डिसऑर्डर जैसे स्लीप एपनिया की जांच करवाएं

दिल की दवाइयां समय पर लें और लाइफस्टाइल में सुधार करें

सोने का तरीका सही रखें, सिर थोड़ा ऊंचा रखें ताकि Fluid चेस्ट की तरफ न बढ़े

रात को सोने से पहले हल्का खाना खाएं

ज्यादा पानी पीने से भी बचना चाहिए

सत्य की जीत: साध्वी प्रज्ञा को 17 साल बाद मिली बड़ी न्यायिक विजय पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने दी बधाई, न्यायपालिका को बताया लोकतंत्र की रीढ़

"भारत की न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर है और वह हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय दिलाने में सक्षम है।"--वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

यह निर्णय केवल एक व्यक्ति की राहत नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, भगवा ध्वज और समूचे राष्ट्रवादी विचारधारा की वैचारिक विजय है।--वरिष्ठ समाजसेवी राजेश

श्री खुराना ने विश्वास जताया कि जो देश विरोधी और हिन्दू विरोधी तत्व इस पूरे खतरनाक षड्यंत्र के पीछे थे, उन्हें ईश्वर उनके कुकर्मों की कठोर सज़ा अवश्य देगा।----

आगरा, संजय सागर सिंह। देश की न्यायपालिका द्वारा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण में सुनाए गए निर्णय के बाद विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक वर्गों में प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने साध्वी प्रज्ञा को न्यायिक विजय की बधाई दी है और इसे "सत्य की जीत" करार दिया है।

वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "यह फैसला साबित करता है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष, निर्भीक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। साध्वी प्रज्ञा जी को मिली राहत न केवल एक निर्दोष के लिए न्याय है, बल्कि उन असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा है, जो वर्षों से बेगुनाही के बावजूद न्याय के इंतजार में हैं।"

समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री खुराना ने यह भी कहा कि यह निर्णय केवल एक व्यक्ति की राहत नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, भगवा ध्वज और समूचे राष्ट्रवादी विचारधारा की वैचारिक विजय है।

श्री खुराना ने कहा कि "यह झूठा मामला न केवल साध्वी जी बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात निर्दोषों के जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित कर गया। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह उस साजिश का हिस्सा था, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व द्वारा 'हिंदुत्व' को निशाना बनाया गया।

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय ने न्याय व्यवस्था में जनता की आस्था को सुदृढ़ किया है और यह स्पष्ट संदेश दिया है कि "भारत की न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर है और वह हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय दिलाने में सक्षम है।"

अपनी बात समाप्त करते हुए श्री खुराना ने विश्वास जताया कि जो देश विरोधी और हिन्दू विरोधी तत्व इस पूरे खतरनाक षड्यंत्र के पीछे थे, उन्हें ईश्वर उनके कुकर्मों की कठोर सज़ा अवश्य देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निर्णय के बाद सर्व समाज में सकारात्मक सोच को बल मिलेगा और निर्दोषों को बिना पक्षपात न्याय मिल सकेगा।

फेफड़ा (लंग्स) कैंसर एक खामोश कातिल है-आओ व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से मिलकर इसपर ठोस कार्यवाही करें

2025 में हमारे पास तकनीकी, ज्ञान व संसाधन है, फेफड़ा कैंसर से लड़ने अब सरकार, समाज, चिकित्सा प्रणाली व आम नागरिकों की इच्छाशक्ति व संकल्प की ज़रूरत है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर पृथ्वी पर 84 लाख योनियाँ विचलित कर रही है, जिसमें मनुष्य का दर्जा सबसे ऊपर है, क्योंकि सृष्टि रचनाकर्ता ने उसे हाईटेक बुद्धि के रूप में अनमोल गिफ्ट दिया है, जिसे हम कुछाग्रता से उपयोग कर अपनीं जीवनशैली को जीने के लिए उस कुछाग्र बुद्धि का उपयोग स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी करना जरूरी हो गया है, क्योंकि वर्तमान डिजिटल युग में अनेक नई-नई बीमारियों का दायरा बढ़ता जा रहा है, हालांकि मेडिकल सुविधाओं का दायरा भी बढ़ता जा रहा, परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि हर मनुष्य को स्वस्थ शरीर रहना ही उसकी अनमोल पूंजी है, जिसके लिए हमें अपने जीवनशैली में अपने शरीर को उन बीमारियों से बचने के लिए शारीरिक स्वस्थ्य रहकर रहना होगा जिसके लिए हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं।चूँकि 1 अगस्त 2025 को विश्व फेफड़ा (लंग्स) कैंसर दिवस है, जो एक खामोश कातिल है, जिसका पता हमें करीब-करीब अंतिम स्टेज पर चलता है, इसलिए हमें अपने जीवनशैली को इस तरह से ढालना है कि इस तरह की बीमारियां हमारे पास फ़टके भी नहीं, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, 2025 में हमारे पास तकनीकी ज्ञान संसाधन हैं, फेफड़ा कैंसर से लड़ने अब सरकार, समाज, चिकित्सा प्रणाली वह आम नागरिक की इच्छा शक्ति व संकल्प की जरूरत है। यह जानकारी मीडिया से उठाई गई है सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती।

साथियों बात अगर हम त अगर हम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 अगस्त 2025 को फेफड़ा कैंसर जनजागरण दिवस की करें तो, हर साल 1 अगस्त को 'वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रभाव को कम करने के लिए एकजुट होना है। फेफड़ों का कैंसर दुनियाँ भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है, और भारत में भी इसकी दरें चिंताजनक हैं।इस गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के बावजूद, फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी कई ऐसी अफवाहें और गलत धारणाएं आज भी समाज में व्याप्त हैं, जो इसकी रोकथाम, शुरुआती पहचान और प्रभावी उपचार में बाधा डालती हैं। इन मिथकों को तोड़ना और वैज्ञानिक तथ्यों को जानना बेहद जरूरी है ताकि हम इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझ सकें और इससे लड़ सकें।विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त 2025 को रुबाधाओं को तोड़ना: शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देनाह थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस थीम का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के शीघ्र निदान और उपचार में असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस हर साल 1 अगस्त को मनानें का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों का समर्थन करना है। इस दिन, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, शैक्षिक अभियान और चिकित्सा पेशेवर और रोगी संगठन फेफड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी साझा करते हैं और इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाते हैं।उद्देश्य:फेफड़ों के कैंसर के शीघ्र निदान और उपचार में असमानताओं को दूर करना है, अन्य महत्वपूर्ण पहलू: (1) फेफड़ों के कैंसर से प्रभावित लोगों को याद करना और उनके साथ खड़े होना (2) फेफड़ों के कैंसर के कारणों, लक्षणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना। (3) स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।(4) शीघ्र निदान और उपचार के महत्व पर जोर देना। फेफड़ों के कैंसर के रोगियों और उनके परिवारों के लिए आवश्यक संसाधनों को प्रदान करना है।

साथियों बात कर हम फेफड़ा कैंसर बढ़ने के

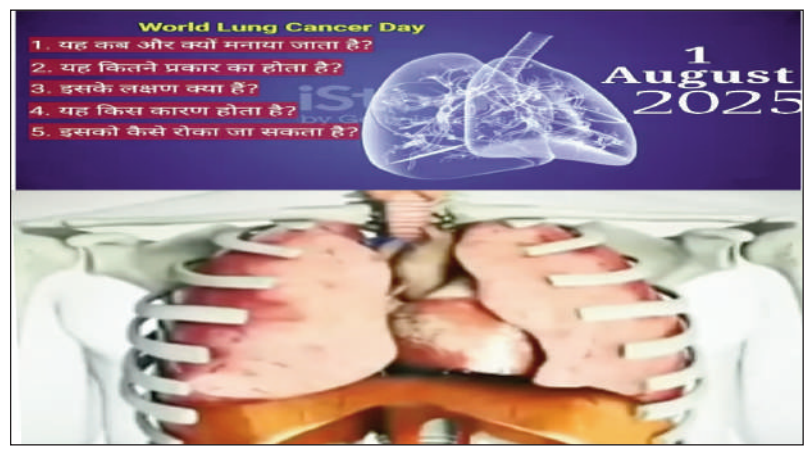

कारणों की करें तो, एक्सपर्ट के मुताबिक, लंग कैंसर के मामलों के बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं जैसे कि, लक्षणों के बारे में जागरूकता की कमी- अधिकांश लोगों को लगातार खांसी, सीने में दर्द और सांस फूलने जैसी समस्या होती है, जो कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में से एक होते हैं। अक्सर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं कि ये लंग कैंसर के संक्रमण होने का इशारा है। इस वजह से बीमारी का इलाज देरी से शुरू होता है।धूम्रपान और तंबाकू का सेवन- डॉक्टर बताते हैं कि भारत के कई राज्यों में बीड़ी, हुक्का और गुटखा जैसी चीजों का सेवन सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। जहां हुक्का पुराने लोगों के घरों में आम हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही युवाओं में सिगरेट और मॉडर्न हुक्का पीने का शौक भी तेजी से बढ़ गया है। हालांकि, युवा इन्हें टशनबाजी में करते हैं लेकिन इससे फेफड़ों का कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। देर से डायग्नोज और स्क्रीनिंग में गड़बड़ी - एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत के अस्पतालों में कैंसर की स्क्रीनिंग हो रही है लेकिन फेफड़ों के कैंसर के लिए कोई नियमित स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। ऐसे में कई बार बीमारी का पता मरीज को तब चलता है जब यह पूरे शरीर में फैल जाती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बीमारी की जांच के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं गलतफहमियां - दरअसल, फेफड़ों के कैंसर को अक्सर धूम्रपान करने वालों की बीमारी माना जाता है। जबकि बीमारी के बढ़ने के पीछे और भी ठोस वजहें हैं। इस वजह से कई बार यदि इंसान को हल्के लक्षण दिख भी रहे हैं, तो वह सोचकर इलाज से बचता है कि वह सिगरेट नहीं पीता है।प्रदूषण- लोग प्रदूषण के बारे में जानते हैं लेकिन इससे कैंसर के जोखिम को नहीं समझ पाते हैं। पिछले कई सालों से लंग कैंसर के मामलों में वृद्धि की प्रमुख वजह पॉल्यूशन रही है।पीएम2.5, इंडस्ट्रियल एमिशन और घर के अंदर के धूंआ भी फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता हैं।

साथियों बात अगर हम फेफड़ा कैंसर की अन्य जानकारी की करें तो (1) फेफड़ा कैंसर की शुरुआती संकेत हमेशा खांसी होना, खांसी में कफ या फिर खून आना।सीने में दर्द होना, गहरी सांस लेने की आदत, आवाज में बदलाव, कमजोरी और थकान महसूस करना।निमोनिया बार-बार होना (2) फेफड़ा कैंसर के लास्ट स्टेज में देखने वाले लक्षण- गर्दन में गांठें।हड्डियों और पसलियों में दर्द।सिरदर्द।चक्कर आना।शरीर का संतुलन खोना, हाथ-पैर में सुन्नपन। बचाव के लिए क्या करें - सिगरेट, शराब जैसी हानिकारक चीजों से परहेज करें।प्रदूषण को घर में न फैलने दें और ऐसे इलाकों में बिना मास्क जाने से बचें।

नियमित जांचें जरूर करवाएं, खासतौर पर वह लोग जो हाई रिस्क ग्रुप जोन में रहते हैं।एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपना खान-पान सख्त रूप से सही रखें।

साथियों बात अगर हम फेफड़ा कैंसर के कारणों उपायों इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने की करें तो-फेफड़ा कैंसरः क्या है यह रोग?-- फेफड़ा कैंसर तब होता है जब फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का निर्माण करती हैं। यह कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं:(नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसरएन एस सी लगभग 85% मामलों में पाया जाता है।स्मॉल सेल लंग कैंसर – तेजी से फैलने वाला प्रकार, 15 पेर्सेंट मामलों में होता है।प्रमुख कारणों में शामिल हैं:(1) धूम्रपान (90 पेर्सेंट मामलों में) (2) वायु प्रदूषण (3) रैडॉन गैस (5) एस्बेस्टस और औद्योगिकरसायन (6) आनुवांशिक जोखिम, आंकड़ों की जुबानीः 2025 में वैश्विक और भारत का परिदृश्य (1) वैश्विक स्थिति (डब्ल्यूएसएससीएल, आईएआरसी के अनुसार): 2025 में अनुमानित 25 लाख नए फेफड़ा कैंसर मामलों का रिकॉर्ड। मृत्यु दरः लगभग 20 लाख लोग इस रोग से मारे गए। (2) पुरुषों में सर्वाधिक घातक कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर के बाद दूसरा।भारत में स्थितिःभारत में 2025 में अनुमानित 1.2 लाख नए मामले।, मृत्यु दर 80 पेर्सेंट के आसपास।शहरी क्षेत्र अधिक प्रभावित, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलाव।आधुनिक जीवनशैली और बढ़ता जोखिम धूम्रपानः फैशन से विनाश धूम्रपान अब केवल तंबाकू नहीं बल्कि ई-सिगरेट, वेपिंग, हुक्का जैसी आधुनिक प्रवृत्तियों में भी फैल चुका है। युवा वर्ग में इसका प्रचलन 'कूल फैक्टर' बन चुका है लेकिन फेफड़ों के लिए यह ज़हर है।वायु प्रदूषणःअदृश्य हत्यारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ा कैंसर का जोखिम 35 पेर्सेंट तक बढ़ जाता है। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर है।शहरीकरण और इनडोर पॉल्यूशन-घरों में अगरबत्ती, रसोई गैस, परफ्यूम, डियोड्रेंट, कीटनाशक जैसे उत्पादों का अत्यधिक उपयोग भी इनडोर एयर क्वालिटी को खराब करता है। खानपान और फेफड़ा कैंसर- प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, हाई ट्रांसफैट डाइट—यह सब शरीर में सूजन और कोशिकीय बदलाव को बढ़ावा देते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिक प्रगति और उपचार के नवाचार- इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, इनआधुनिक तकनीकों ने कीमोथेरेपी के बाद की दुनिया को बदला है, लिक्विड बायोप्सी और एआई आधारित डिटेक्शन,, अब ब्लड सैंपल से ही प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान संभव है।

साथियों बातें कर हम कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की करें तो, चिकित्सा पद्धतियाँ: इलाज की आधुनिक दिशा (1) सर्जरीःप्रारंभिक चरण में कैंसरयुक्त ऊतक हटाना (2) कीमोथैरेपीःरसायनों द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारना (3) रेडिएशन थेरेपीःऊर्जा तरंगों से ट्यूमर को नष्ट करना (4) टारगेटड थेरेपीःजिन कैंसरों में विशिष्ट म्यूटेशन हो, उनके लिए (5) इम्यूनथेरेपीःरोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर कैंसर से लड़ने के लिए सक्षम बनाना।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि फेफड़ा (लंग्स) कैंसर एक खामोश कातिल है- आओ व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से मिलकर इसपर ठोस कार्यवाही करें विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त 2025- तंबाकू मुक्त जीवन, स्वस्थ्य हवा व स्वास्थ्य समता का सामाजिक नैतिक व नीतिगत आवाहन, 2025 में हमारे पास तकनीकी, ज्ञान व संसाधन है, फेफड़ा कैंसर से लड़ने अब सरकार, समाज, चिकित्सा प्रणाली व आम नागरिकों की इच्छा शक्ति व संकल्प की ज़रूरत है।

Ather 450S का नया वेरिएंट बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगा 161km की रेंज

Ather ने जुलाई 2025 में Rizta S 3.7kWh लॉन्च किया जो Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। इस नए वेरिएंट में 3.7kWh बैटरी पैक है जो IDC-प्रमाणित रेंज को 161 किमी तक बढ़ाता है। स्कूटर में 5.4kW इलेक्ट्रिक मोटर है और यह 3.9 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की गति पकड़ सकता है। कीमत 1.46 लाख रुपये है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी Ather ने जुलाई 2025 की शुरुआत में Rizta S 3.7kWh को लॉन्च किया था। यह नया वेरिएंट एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप में जरूरी जुड़ाव है। इसके डिजाइन और फीचर्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Ather 450S 3.7 में क्या है नया?

इसे बड़ी बैटरी पैक और बेहतर रेंज के साथ लेकर आया गया है। इसमें एक बड़ा 3.7kWh बैटरी पैक दिया गया है। पहले यह बैटरी केवल 450X में मिलती थी। इस अपग्रेड से IDC-प्रमाणित रेंज 450S 2.9 के 115 किमी से बढ़कर 161 किमी तक पहुंच गई है। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जिन्हें लंबी दूरी की रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश रहती है।

पहले जैसा है परफॉर्मेंस

Ather 450S के परफॉर्मेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी 22Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला 5.4kW इलेक्ट्रिक मोटर दिया है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.9 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 90kph है। इसमें चार राइड मोड स्मार्ट इको, इको, राइड और स्पोर्ट दिए गए हैं, जो अलग-अलग राइडिंग स्थितियों के लिए अनुकूल हैं।

डिजाइन और फीचर्स पहले जैसे

Ather 450S को बैटरी अपडेट देने के अलावा बाकि चीजें पहले की तरह ही है। इसके डिजाइन और फीचर्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 7-इंच का LCD डैश भी मिलता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, हिल-होल्ड, फॉल सेफ और एथरस्टैक OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी है किमत?

Ather 450S के इस नए वेरिएंट को 1.46 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। यह 450S 2.9 की तुलना में 16,000 रुपये ज्यादा महंगा है। कंपनी इसे खरीदने वालों को एथर एटसेवेनटी (Ather Eight70) वारंटी पैकेज भी दे रही है, जो बैटरी को 8 साल या 80,000 किमी के लिए कवर करता है, जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत बैटरी स्वास्थ्य की गारंटी दी गई है। डिलीवरी अगस्त 2025 में शुरू होगी, और बुकिंग अब ऑनलाइन और एथर डीलरशिप पर खुली हैं।

टाटा हैरिअर ईवी की भारत में डिलीवरी शुरू, बढ़ते डिमांड के चलते 3 महीने पहुंचा वेटिंग पीरियड

टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक SUV Tata Harrier EV को लॉन्च किया है और अब इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। यह भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक SUV है जिसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम है। यह दो बैटरी पैक और कई शानदार फीचर्स के साथ आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 21.49 लाख रुपये से शुरू होती है।

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक SUV, Tata Harrier EV को लॉन्च किया है। अब कंपनी ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। यह भारत की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही, इसमें कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे बाकियों से ज्यादा शानदार बनाते हैं। आइए टाटा हैरियर ईवी के बारे में विस्तार में जानते हैं।

कितनी है कीमत?

Tata Harrier EV को 21.49 लाख रुपये से लेकर 30.23 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लेकर आया गया है। इसके साथ ही यह टाटा मोटर्स की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है।

बैटरी पैक और रेंज

Tata Harrier EV को दो बैटरी पैक के साथ पेश किया जाता है, जो 65 kWh और 75 kWh है। इसके डुअल-मोटर कॉन्फिगरेशन में फ्रंट मोटर 155.8 hp की पावर, जबकि रियर मोटर 234.7 hp की पावर जनरेट होता है। इसके 75 kWh RWD वैरिएंट की रेंज 627 किमी, 75 kWh AWD वैरिएंट की रेंज 622 किमी और 65 kWh RWD वैरिएंट की रेंज 538 किमी है।

Tata Harrier EV के फीचर्स

इसमें ऑफ-रोड कैपेसिटी के लिए छह ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जिसमें सैंड (रेत), स्नो (बर्फ), रॉक (चट्टान), मड/रट्स (कीचड़/खांचे), नॉर्मल (सामान्य) और कस्टम (अनुकूलित) है। यह ड्राइविंग मोड अलग-अलग इलाकों के अनुरूप पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सस्पेंशन सेटिंग्स को संशोधित करते हैं, जिससे किसी भी तरह की सड़क पर बेहतर कंट्रोल मिलता है।

इसमें 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.53-इंच का हरमन-सोर्स्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शनैलिटी वाली ड्राइवर सीट, एक वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, विंडो सनब्लाइंड्स, एम्बिएंट लाइटिंग समेत और भी कई चीजें मिलती है।

सफर के दौरान पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, डिस्क वाइपिंग के साथ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, ऑटो हेडलैंप और लेवल 2 ADAS के सूट शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ने की भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा, जानें ऑटोमोबाइल बाजार पर क्या होगा असर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत अब ट्रम्प की व्यापार रणनीति के तहत टैरिफ का सामना करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस फैसले का भारत के ऑटोमोबाइल बाजार पर असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका भारत से ऑटो पार्ट्स के निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 अगस्त से प्रभावी होने वाले भारत से निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारत ट्रम्प की लिबरेशन डे व्यापार रणनीति के तहत ज्यादा टैरिफ का सामना करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला नया देश बन गया है। इसके तकत बढ़े हुए पारस्परिक समझौतों के जरिए से अमेरिकी व्यापार साझेदारी को पुनर्गठित करना है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि इसका भारत के ऑटोमोबाइल बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा?

मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि याद रखें, जबकि भारत हमारा दोस्त है, हमने वर्षों से उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं, दुनिया में सबसे अधिक हैं, और उनके पास किसी भी देश के सबसे कड़े और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा, उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है, और चीन के साथ-साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्या बंद करे, यह सब अच्छा नहीं है। इसलिए भारत उपरोक्त के लिए 1 अगस्त से शुरू होने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ प्लस जुर्माना का भुगतान करेगा।

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार पर असर

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से निर्यात किए गए ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 7.35 बिलियन डॉलक के पार्ट भेजे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.4 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, अमेरिका से भारत को ऑटो कंपोनेंट के आयात का मूल्य 1.65 बिलियन डॉलर रहा। ऐसे में इस टैरिफ के लगने के बाद सोना कॉमस्टार और अन्य जैसे ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, यह कनाडा, जापान और अन्य जैसे प्रतिस्पर्धी बाजारों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ उनकी स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा, अमेरिकी बाजार में निर्यात की संभावनाओं की तलाश कर रहे OEMs (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स) को भी यूरोप जैसे अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस सूची में रॉयल एनफील्ड, होंडा और अन्य प्रमुख दोपहिया निर्माता शामिल हैं जो अमेरिकी बाजार में मोटरसाइकिल की मांग का लाभ उठाना चाहते हैं।

Uber की चलती-फिरती लग्जरी लाउंज Motorhomes लॉन्च, TV से लेकर बाथरूम तक की सुविधा

Uber ने भारत में इंटरसिटी सर्विस का विस्तार करते हुए इसे 3000 से अधिक मार्गों पर शुरू किया है। इसके साथ ही Uber ने खास Uber Intercity Motorhomes भी लॉन्च किए हैं जो यात्रा को आरामदायक बनाते हैं। ये Motorhomes दिल्ली-NCR से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए उपलब्ध हैं और इनमें मनोरंजन छोटा बाथरूम माइक्रोवेव और मिनी-रेफ्रिजरेटर जैसी सुविधाएं हैं।

नई दिल्ली। भारत में लंबी दूरी की रोड ट्रिप को मजेदा बनाने के लिए Uber ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी अपनी इंटरसिटी सर्विस को पूरे भारत में 3,000 से ज्यादा रास्तों तक फैला दिया है। इसका मतलब है कि अब आप पहले से ज्यादा 50 प्रतिशत ज्यादा शहरों के बीच Uber से सफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं Uber ने इंटरसिटी के दायरे को बढ़ाने के साथ ही खास तरह से डिजाइन किए गए Uber Intercity Motorhomes भी लॉन्च किए है। इन्हें पूरी तरह से एक छोटे से घर जैसा बनाया गया है।

पिछले 12 महीनों में Intercity का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुंबई-पुणे, दिल्ली-आगरा, बेंगलुरु-मैसूर, लखनऊ-कानपुर और अहमदाबाद-वडोदरा रूट पर किया गया। इसके साथ ही बाकि जगहों पर भी लोग सफर के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वीकेंड पर किया जा रगा है। इसके साथ ही इसके जरिए लोग दिवाली, होली, ईद और गर्मियों में शादी के सीजन जैसे त्योहारों पर अपने नेटिव प्लेस पर जाने के लिए कर रहे हैं। वहीं, वन-वे इंटरसिटी राइड्स अभी भी परिवार और दोस्तों से मिलने, बिज़नेस ट्रिप पर जाने या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होती हैं।

Uber ने इंटरसिटी को बढ़ावा देने के लिए एक खास ऑफर के तहत Motorhomes को लॉन्च किया है। आप इन्हें दिल्ली-NCR से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए बुक कर सकते हैं। इसमें आपको वह सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो सामान्य इंटरसिटी राइड में मिलती हैं, जैसे पहले से बुकिंग (Reserve), रास्ते में रुकने की सुविधा, आपकी लोकेशन को ट्रैक करना और 24x7 हेल्पलाइन सपोर्ट। ये इंटरसिटी Motorhomes 7 अगस्त से 6 सितंबर तक उपलब्ध रहेंगे। इनकी बुकिंग 4 अगस्त से उबर ऐप पर शुरू हो जाएगी, जहां आपको इनका एक खास आइकॉन दिखेगा।

Motorhomes में क्या-क्या मिलेगा?

इसमें एक ड्राइवर और एक हेल्पर होगा। इसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इन गाड़ियों में मनोरंजन और आराम के लिए टेलीविजन, छोटा बाथरूम, माइक्रोवेव और मिनी-रेफ्रिजरेटर भी मिलेगा। यह एक तरह से चलती-फिरती प्राइवेट लाउंज है, जो आपके वीकेंड ट्रिप या किसी खास मौके पर यात्रा को यादगार बना देगी।

एमबीबीएस का विकल्प

विजय गर्ग

यदि आप स्वास्थ्य सेवा में कैरियर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन एमबीबीएस का पीछा नहीं करना चाहते हैं, तो कई उत्कृष्ट विकल्प हैं। ये विकल्प अक्सर मजबूत कैरियर की संभावनाओं, अच्छे वेतन की पेशकश करते हैं, और आपको स्वास्थ्य सेवा के एक विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की अनुमति देते हैं। यहां एमबीबीएस के कुछ लोकप्रिय विकल्प दिए गए हैं: मैं। संबद्ध स्वास्थ्य पेशे (स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रम): ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें नैदानिक, तकनीकी, चिकित्सीय और सहायता सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इनमें से कई पाठ्यक्रमों के लिए नीट युजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) की आवश्यकता नहीं है।

नर्सिंग (वी एस सी. नर्सिंग): रोगी की देखभाल, चिकित्सा प्रक्रियाओं और रोगी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अत्यधिक सम्मानित पेशा। विश्व स्तर पर नर्सों की उच्च मांग है।

फार्मेसी (बी.फरम): दवाओं की दुनिया पर केंद्रित है, जिसमें उनके विकास, विनिर्माण, वितरण और सुरक्षित उपयोग शामिल हैं। फार्मासिस्ट अस्पतालों, खुदरा, अनुसंधान या दवा उद्योग में काम कर सकते हैं।

फिजियोथेरेपी (बीपीटी - बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी): चिकित्सीय अभ्यास और उपचार के माध्यम से रोगियों में शारीरिक पुनर्वास, आंदोलन को बहाल करना और कार्य करना शामिल करता है। इस क्षेत्र में मांग बढ़ रही है, खासकर खेल और पुनर्वास में।

व्यावसायिक चिकित्सा (बीओटी - बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी): शारीरिक, मानसिक या विकासात्मक स्थितियों वाले व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल विकसित करने और स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है।

चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (बी एस सी एमएलटी): नैदानिक परीक्षणों और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना, रोगों का निदान करने के लिए शारीरिक तरल पदार्थ और ऊतकों का विश्लेषण करना।

रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी (रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी): एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी नैदानिक इमेजिंग तकनीकों को शामिल करता है।

ऑप्टोमेट्री: आंखों की देखभाल, दृष्टि सुधार और आंखों की स्थिति का निदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

ऑडियोलॉजी और स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी (B.Sc. ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी): श्रवण और भाषण विकारों के निदान और उपचार के साथ सौदे।

डायलिसिस टेक्नोलॉजी (बी एस सी. डायलिसिस थेरेपी या डिप्लोमा): डायलिसिस मशीनों के संचालन और गुर्दे की बीमारी के रोगियों को देखभाल प्रदान करने में माहिर हैं।

ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी (बी एस सी. या डिप्लोमा): सर्जिकल प्रक्रियाओं में सहायता करना और ऑपरेशन थियेटर का प्रबंधन करना शामिल है।

कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी: ओपन-हार्ट सर्जरी के दौरान हार्ट-लंग मशीनों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है।

श्वसन चिकित्सा प्रौद्योगिकी: श्वसन विकारों वाले रोगियों का इलाज करना शामिल है। द्वितीय। पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली (अक्सर भारत में नीट युजी की आवश्यकता होती है): ये रास्ते भी अपने-अपने सिस्टम के भीतर एक योग्य डॉक्टर बनने का कारण बनते हैं।

बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस): दंत चिकित्सा देखभाल, मौखिक स्वास्थ्य और सर्जरी पर केंद्रित है।

बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस): प्राकृतिक उपचार और समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करके पारंपरिक भारतीय चिकित्सा, आयुर्वेद पर ध्यान केंद्रित करता है।

बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस): होम्योपैथिक चिकित्सा प्रथाओं और उपचारों से संबंधित है।

बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीयूएमएस): यूनानी चिकित्सा पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न हुई थी।

बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बीऐनवाईऐस): समग्र कल्याण के लिए प्राकृतिक उपचार और योग का अध्ययन करता है।

पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक (बी वीऐससी): जानवरों के उपचार और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। तृतीय। अन्य हेल्थकेयर-संबंधित क्षेत्र:

जैव प्रौद्योगिकी (बी एस सी जैव प्रौद्योगिकी): आनुवंशिक इंजीनियरिंग, दवा की खोज और निदान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को शामिल करता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य (बी एस सी/एम एच सी): जागरूकता अभियानों, रोग प्रवृत्ति विश्लेषण और नीति विकास के माध्यम से जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

क्लिनिकल रिसर्च: इस क्षेत्र में पेशेवर (जैसे, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स - सीआर ऐएस) नई दवाओं और उपचारों के लिए नैदानिक परीक्षणों का समन्वय और निगरानी करते हैं।

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग: स्वास्थ्य उपकरणों और प्रणालियों को डिजाइन और बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान के साथ इंजीनियरिंग सिद्धांतों को जोड़ती है।

पोषण और आहार विज्ञान (बी एस सी पोषण और आहार विज्ञान): स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन के लिए क्राफ्टिंग आहार पर ध्यान केंद्रित करता है।

अस्पताल और हेल्थकेयर प्रबंधन: स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रशासनिक और प्रबंधकीय पहलुओं में रुचि रखने वालों के लिए।

मनोविज्ञान (बी एस सी. मनोविज्ञान): परामर्श, नैदानिक मनोविज्ञान (आगे की शिक्षा के साथ), या स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स के भीतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता में करियर का कारण बन सकता है।

फोरेंसिक विज्ञान: चिकित्सा-कानूनी पहलुओं में काम करना शामिल कर सकता है, जैसे कि विष विज्ञान या डीएनए प्रोफाइलिंग। एक विकल्प चुनते समय, अपने हितों, विज्ञान के लिए योग्यता, रोगी बातचीत वरीयताओं और कैरियर के लक्ष्यों पर विचार करें। एक सूचित निर्णय लेने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, नौकरी की संभावनाओं और कमाई की क्षमता पर शोध करें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

आखिर कब समझेंगे हम प्रकृति की मूक भाषा

विजय गर्ग

पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन प्रजातियों के लुप्त होने का सीधा असर समस्त मानव सभ्यता पर पड़ना अवश्यम्भावी है। प्रदूषित हो रहे पर्यावरण के आज जो भयावह खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो और हमें यह स्वीकार करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि प्रकृति आखिर है क्या ? प्रकृति के तीन प्रमुख तत्व हैं जल, जंगल और जमीन, जिनके बगैर प्रकृति अधूरी है और

विम्बना ही है प्रकृति के इन तीनों ही तत्वों का इस कदर दोहन किया जा रहा है कि इसका संतुलन डगमगाने लगा है, जिसकी परिणति अक्सर भयावह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने भी आने लगी है। प्राकृतिक साधनों के अंधाधुंध दोहन और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही नतीजा है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं। पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी कार्यक्षमता भी इससे प्रभावित हो रही है। लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा

बीमारियों के इलाज पर ही खर्च हो जाता है।

प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, जंगल, वन्य जीव और वनस्पति, इन सभी का संरक्षण अत्यावश्यक है। दुनियाभर में पानी की कमी के गहराते संकट की बात हो या ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के तपने की अथवा धरती से एक-एक कर वनस्पतियों या जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने की, इस तरह की समस्याओं के लिए केवल सरकारों का मुंह ताकते रहने से ही हमें कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि प्रकृति संरक्षण के लिए हम सभी को अपने-अपने स्तर पर अपना योगदान देना होगा। प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय से भयानक तूफानों, बाढ़, सूखा भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। हमारे जो पर्वतीय स्थान कुछ सालों पहले तक शांत और स्वच्छ हवा के लिए जाने जाते थे, आज वहां भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ठंडे इलाकों के रूप में विख्यात पहाड़ भी अब तपने लगने हैं, वहां भी जल संकट गहराने लगा है, वहां भी बाढ़ का ताण्डव देखा जाने लगा है। इसका एक बड़ा कारण पहाड़ों में भी विकास के नाम पर जंगलों का सफाया करने के साथ-साथ पहाड़ों में बढ़ती पर्यटकों की भारी भीड़ भी है। कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा सामने आने पर हम आदतन प्रकृति को कोसना शुरू कर देते हैं लेकिन हम नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रह-रहकर अपना रौद्र रूप दिखाकर हमें सचेत करने का प्रयास करती रही है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति से साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। प्रकृति हमारी मां के समान है, जो हमें अपने प्राकृतिक खजाने से ढ़ेरों बहुमूल्य चीजें प्रदान करती है लेकिन अपने स्वार्थों के चलते हम अगर खुद को ही प्रकृति का स्वामी समझने की भूल करने लगे हैं तो फिर भला प्राकृतिक तबाही के लिए प्रकृति को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं बल्कि दोषी तो हम स्वयं हैं, जो इतने साधनपरस्त और आलसी हो चुके हैं कि अगर हमें अपने घर से थोड़ी ही दूरी से भी कोई सामान लाना पड़े तो पैदल चलना हमें गवारा नहीं। इस छोटी सी दूरी के लिए भी हम स्कूटर या बाइक का सहारा लेते हैं। छोटे-मोटे कार्यों की पूर्ति के लिए भी निजी यातायात के साधनों का उपयोग कर हम पैट्रोल, डीजल जैसे धरती पर ईंधन के सीमित स्रोतों को तो नष्ट कर ही रहे हैं, पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे है।

ट्रंप टैरिफ की चुनौती को अवसर में बदल

राजेश जैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 20 से 25 प्रतिशत तक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत को साफ तौर पर 1 अगस्त तक की समय सीमा दी है। अगर तब तक कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ तो भारतीय उत्पादों पर 16 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। यह शुल्क पहले से लागू 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ के अलावा होगा, जिससे कुल शुल्क 30 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चेतावनी है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा—खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, जेम्स-ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर पर। जब एक अमेरिकी ग्राहक भारतीय गारमेंट या फार्मा उत्पाद खरीदने की सोचेगा, तो उसे 25% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर भारत हर साल अमेरिका को लगभग 9 अरब डॉलर के कपड़े निर्यात करता है। ऐसे में अगर टैरिफ बढ़ गया, तो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देश इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें शुल्क रियायतें दे रखी हैं।

यह टैरिफ संकट केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर निवेश पर भी पड़ सकता है। भारत की छवि अनिश्चित व्यापारिक वातावरण वाले देश की बन सकती है, जिससे संभावित विदेशी निवेशक हिचक सकते हैं।

भारत की रणनीति

भारत की ओर से संतुलन बनाने की कोशिशें जारी हैं। भारत चाहता है कि टैरिफ 10% से कम रखा जाए और बदले में अमेरिका को कुछ क्षेत्रों में रियायतें दी जाएं।

हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोलेगा। अमेरिका लंबे समय से इन क्षेत्रों में प्रवेश चाहता रहा है लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं होगा।

भारत गैर-कृषि क्षेत्रों में समझौते के लिए तैयार है और अमेरिका को यह भी प्रस्ताव दे चुका है कि यदि शुल्क घटाए जाते हैं तो भारत अमेरिकी औद्योगिक सामानों पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने को तैयार है। इतना ही नहीं, भारत ने बोइंग से विमान खरीदने की संभावना भी जताई है ताकि व्यापार घाटा संतुलित हो सके।

संभावनाएं और उम्मीदें

इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिका की ट्रेड टीम 25 अगस्त को भारत आ रही है। उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर तक दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते तक पहुंच सकते हैं। पिछली बैठक वॉशिंगटन में हुई थी, जहाँ भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल और अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने विस्तृत चर्चा की थी। ट्रंप के हालिया बयान भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। उनका यह कहना कि "अब मैं इंचार्ज हूं और यह सब खत्म होगा", संकेत देता है कि वह भारत को शीघ्र समझौते के लिए बाध्य करना चाहते हैं जबकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ किया है कि भारत किसी भी समझौते पर दबाव में हस्ताक्षर नहीं करेगा। भारत सिर्फ उन्हीं शर्तों पर समझौता करेगा जो देश के हित में हों और पूरी तरह से परखी गई हों।

संकट या अवसर ?

यह संकट भारत के लिए एक अवसर भी है। यही समय है जब 'मेक इन इंडिया', पीएलआई स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जाए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह टैरिफ संकट एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। साथ ही, भारत को पारंपरिक बाजारों के साथ-साथ नए निर्यात गंतव्य भी तलाशने होंगे—अफ्रीका, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत के लिए संभावनाओं से भरे हुए हैं।

कूटनीति की कसौटी

कूटनीतिक स्तर पर भारत की भूमिका और भी ज़िम्मेदार हो गई है। भारत और अमेरिका के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं—हम रक्षा, तकनीक, साइबर सुरक्षा और 'क्वाड' जैसे बहुपक्षीय मंचों पर साझेदार हैं। अमेरिका के लिए भी यह समझदारी भरा कदम होगा कि वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को खराब न होने दे।

जब युद्ध तलवारों से नहीं, व्यापार की शतरंज पर लड़ा जाए तो हर चाल का असर करोड़ों लोगों की जेब और भविष्य पर पड़ता है। अगर व्यापार युद्ध है तो समझौता उसकी शांति है—लेकिन शांति हमारी शर्तों पर होनी चाहिए, झुकाव की मुद्रा में नहीं। भारत को इस लड़ाई में अपनी ज़मीन पर टिके रहकर, नीतिगत मजबूती और कूटनीतिक संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी हम इस टैरिफ की चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे।

राजेश जैन

एआई तकनीक मौलिक चिंतन की जगह नहीं ले सकती है

विजय गर्ग

एआई तकनीक मौलिक चिंतन की जगह नहीं ले सकती है। वह एक कैल्कुलेटर की तरह गणनाएं कर सकती है, खुद में दर्ज डाटा की स्मृतियों के बल पर एक सवाल के कई जवाब दे सकती है, उनमें हर बार कोई नयापन ला सकती है, लेकिन जब बात किसी नई स्थिति में मौलिक उपाय सुझाने की आती है, तो मामला फंस जाता है।

करीब पौने तीन साल पहले 30 नवंबर, 2022 को जब ओपन एआई नामक कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमता यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एआई संचालित पहला भाषाई चैटबॉट-चैटजीपीटी लॉन्च किया था, तो सनसनी फैलाने वाले इस आविष्कार को लेकर सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं शिक्षा जगत से ही मिली थीं। पदार्पण के पांच दिनों के अंदर दुनिया भर में चैटजीपीटी के दस लाख लोगों के ग्राहक बनने के बावजूद शुरुआती दिनों में ही अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में चैटजीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गयी थी। न्यूयॉर्क और सिएटल स्थित विश्वविद्यालयों-कॉलेजों के प्रशासन ने सुनिश्चित किया था कि उनके छात्र कैंपस में मौजूद रहने के दौरान अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप तथा सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैटजीपीटी नहीं खोल पाएं। अभी इस चर्चा का महत्व यह है कि चैटजीपीटी को वजूद में लाने वाली कंपनी- ओपनएआई के संस्थापक और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने दावा किया है कि जिस तेजी से एआई तकनीक दुनिया में पांव पसार रही है, उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाएगा।

वैसे तो भारत से ज्यादा ऑल्टमैन का बयान अमेरिकी-यूरोपीय विश्वविद्यालयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय शिक्षा मानकों वाली पढ़ाई के बल पर वे दुनिया भर के छात्रों के आकर्षण के केंद्र में रहे हैं। दूसरी बार सत्ता में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के मुद्दे और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में वैचारिक स्वतंत्रता को लेकर जिस तरह की भिड़ंत के मूड में हैं, अगर उसे दरकिनार रख दें तो इन मुल्कों के आला दर्जे के विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा अभी तक तो बची रही है। लेकिन एआई के तरह-तरह के मॉडल बनाने वाली कंपनियां जिस तेजी से शिक्षा के लिए चुनौतियां पेश कर रही हैं, उससे ऑल्टमैन द्वारा खड़ी की गई यह चेतावनीपूर्ण आशंका अपनी जगह सही लगती है कि पारंपरिक शिक्षा का भविष्य सच में खतरे में है।

अध्यापकों के लिए चुनौती यह है कि कैसे वे अपने छात्रों को एआई के इस्तेमाल से रोकें। स्कूल-कॉलेज के सामान्य पाठ्यक्रमों में ही नहीं, पीएचडी के लिए शोधकार्य कर रहे छात्र तक धड़ल्ले से एआई की मदद अपने शोधपत्र आदि में ले रहे हैं। ऐसा एक चर्चित मामला अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय का है, जहां पीएचडी के एक छात्र को परीक्षा में एआई के इस्तेमाल का दोषी पाते हुए निष्कासित कर दिया गया था। शोधकार्यों की जटिलता, पवित्रता और महत्ता के मद्देनजर इस कार्रवाई को उचित ठहराया जा सकता है, हालांकि छात्र ने एआई संबंधी जांच में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय पर उचित प्रक्रिया नहीं अपनाने और प्रोफेसर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इससे उलट एक मामला नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी का है, जहां एक वरिष्ठ छात्रा ने अपने प्रोफेसर के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई कि पढ़ाने के लिए उन्होंने जिस सामग्री का इस्तेमाल किया, वह हूबहू एआई टूल्स से तैयार की गई थी। छात्रा ने इस आधार पर अपनी ट्यूशन फीस वापसी की मांग की। प्रोफेसर ने कई एआई के इस्तेमाल की बात स्वीकार की और पारदर्शिता की जरूरत को माना।

इन घटनाओं की रोशनी में देखें, तो ऑल्टमैन जिस चुनौती और

आशंका की बात कह रहे हैं, वह अपनी जगह सही लगती है। इसका अहसास होता है कि जिस तरह से और जिस तरह की शिक्षा ऊंचे से ऊंचे विश्वविद्यालयों में दी जा रही है, अगर उसका ढर्रा नहीं बदला गया, तो छात्र अगले पांच-सात वर्षों में एआई गुरु के पांव लगते ही नजर आएंगे। इसलिए पारंपरिक शिक्षा के केंद्रों और मॉडल को बचाना है, तो जिस युद्ध स्तर पर एआई उसे खत्म करने पर तुला है, उससे कई गुना ज्यादा ताकत से उसे बचाने की जंग छेड़नी होगी।

प्रश्न है कि फिर ऐसा क्या करना होगा, जिससे उच्च शिक्षा की नैतिकता, पवित्रता और अक्षुण्णता कायम रह सके। हमें ठहरकर सोचना होगा कि आखिर उच्च शिक्षा मूल स्वरूप में अपने छात्रों को क्या देती है। आज जिस तरह का शिक्षा का मॉडल हमारे देश में अपनाया जा रहा है, उसमें उच्च शिक्षा का मतलब रैंकिंग और तरह-तरह के सितारे लगाने वाली शोध प्रणाली को अपनाने पर जोर है, वह कागजों पर आला दर्जे की लगती है। ऐसे नियमों-मानदंडों का पालन करने वाले शिक्षण संस्थान बड़े जोरशोर से अपनी रैंकिंग का ढिंढोरा पीटते हैं। इसके बल पर वे पैसा फूंकने वाले छात्रों को अपनी ओर खींचने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन इन्हीं शिक्षण संस्थानों के छात्र न तो रोजगार बाजार में अपनी योग्यता साबित कर पाते हैं और न ही उनके शोध इंडस्ट्री में किसी काम के माने जाते हैं। अगर ये शिक्षण संस्थान इतने ही काबिल होते, तो इन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं इनके छात्र आज तक गूगल, ट्विटर, टिकटॉक, डीपसीक या चैटजीपीटी जैसा कोई मॉडल बना पाए। क्यों नहीं आईफोन भारत में बना, क्यों नहीं ऐसी सौर ऊर्जा तकनीक हमारे देश में विकसित हुई कि दुनिया उसकी मुरीद हो जाती। नकल करना एक बात है, मौलिक चिंतन (क्रिटिकल थिंकिंग) से कोई आविष्कार करना दूसरी बात है। समस्या यह है कि आज अगर कोई शिक्षक भी शोध का मौलिक प्रस्ताव या विचार लेकर अपने संस्थान की शोध-प्रबंधन इकाई के पास सीड-ग्रांट आदि के लिए जाता है, तो उसे यह कहकर दुत्कार दिया जाता है कि ऐसा तो अमेरिका में नहीं हुआ, आप यह प्रस्ताव नाहक ही हमारे पास लेकर आ गए। मौलिक चिंतन और मौलिक शोध को लेकर कायम इसी नकारात्मक सोच का नतीजा है कि हमारे ज्यादातर विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने की जगहों में तब्दील हो गए हैं।

ध्यान रखिए कि एआई तकनीक मौलिक चिंतन की जगह नहीं ले सकती है। वह एक कैल्कुलेटर की तरह गणनाएं कर सकती है, खुद में दर्ज डाटा की स्मृतियों के बल पर एक सवाल के कई जवाब दे सकती है, उनमें हर बार कोई नयापन ला सकती है, लेकिन जब बात किसी नई स्थिति में मौलिक उपाय सुझाने की आती है, तो मामला फंस जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि चैटजीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास इतिहास संबंधी काफी डाटा होता है, लेकिन वे इतिहास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को सही तरीके से नहीं समझते हैं। ऐसे में या तो वे सवाल की भाषा और उपलब्ध डाटा के आधार पर ऐसा करीबी जवाब देने की कोशिश करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। इन मॉडल्स से किसी मौलिक उत्तर की उम्मीद बेमानी है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब,

गिरती छतें, टूटते सपने: क्या गरीबों की जान की कोई क़ीमत नहीं?

अशोक कुमार झा

क्या आपने कभी सुना है कि किसी कलेक्टर का घर गिर गया हो ? किसी मंत्री के आवास की छत भरभरा कर ढह गई हो ? या किसी नौकरशाह की कोठी किसी बारिश में ढह गई हो ? नहीं ना ? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। उनके मकानों की समय-समय पर मरम्मत होती है, भवनों की तकनीकी जांच होती है, अगर मरम्मत के लायक नहीं होते तो या तो उन्हें खाली करवा लिया जाता है, या पूरी तरह से नया भवन बना दिया जाता है — और यह सब होता है सरकार के बजट और सिस्टम की प्राथमिकता के तहत।

लेकिन जब बात उन भवनों की आती है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मजदूर परिवार अपना जीवन बिताते हैं, जहाँ आम नागरिक अपने परिवार की उम्मीदें लेकर रहते हैं — तो वही भवन अक्सर हादसों के इंतजार में खड़े दिखाई देते हैं। दरारें दिखती हैं, प्लास्टर झड़ता है, छतें सीलन से सड़ती हैं, लेकिन व्यवस्था तब तक नहीं जागती जब तक कि कोई हादसा न हो जाए।

ताजा उदाहरण: झालावाड़ का भयावह हादसा राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के मनोहरथाना ब्लॉक स्थित पिपलोदी के सरकारी स्कूल में छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। 9 से अधिक घायल हुए। ये बच्चे उस इमारत में पढ़ने आए थे जिसे 'विद्यालय' कहा जाता था, लेकिन वह भवन कब्रगाह में बदल गया। यह कोई पहली घटना नहीं है।

कुछ ही हफ्ते पहले झारखंड की राजधानी रांची में भी एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से कई लोग घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। ये घटनाएं अलग-अलग राज्यों से हैं, लेकिन इनकी जड़ें एक ही हैं — लापरवाही, भ्रष्टाचार और गरीबों के जीवन की उपेक्षा।

वास्तव में गिरता क्या है — छत या व्यवस्था ? जब किसी स्कूल की छत गिरती है, जब किसी सड़क का पुल टूटता है, जब कोई मकान भरभराकर गिरता है — तब दरअसल सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं गिरते। गिरती है हमारी प्रशासनिक संवेदनशीलता, नीतियों की निष्क्रियता, और सबसे बढ़कर वो भरोसा जो जनता अपने नेताओं, अफसरों और शासन पर करती है।

किसी भी सरकारी भवन को बनाने, उसके रखरखाव, निरीक्षण, और सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर PWD (लोक निर्माण विभाग), नगर निगम, शिक्षा विभाग, और जिला प्रशासन जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इन भवनों की नियमित तकनीकी जांच, सेफ्टी ऑडिट, और जरूरी मरम्मत कार्य महज कागजों में ही होता है।

जो दिखता है, उसे सजाया जाता है; जो अनदेखा है, वह मौत बन जाता है

आप संसद भवन को देखिए — नया बना, भव्य और तकनीकी रूप से सुरक्षित। विधानसभाएं वातानुकूलित, सुसज्जित और टिकाऊ हैं। हाईकोर्ट, सचिवालय, मंत्रालय — सबका कायाकल्प होता रहता है। क्योंकि वहाँ बैठने वाले VIP होते हैं। उनकी जान की क़ीमत होती है। लेकिन किसी आंगनबाड़ी केंद्र की बात कीजिए, किसी पंचायत भवन की, या किसी जिला स्कूल की — वहाँ तो अक्सर दीवारें झड़ती मिलती हैं, फर्श उखड़ा होता है, और छत में दरारें साफ़ दिखाई देती हैं। लेकिन जब तक कोई हादसा न हो जाए, अधिकारी दौरे पर नहीं आते। ये भवन भरोसे की कब्रगाह बने रहते हैं।

सवाल यह नहीं कि छत क्यों गिरी — सवाल यह है कि चेतावनी के बावजूद क्यों नहीं रोका गया ? झालावाड़ के हादसे में बच्चों ने खुद बताया कि छत में दरार है, लेकिन शिक्षकों ने उन्हें धमका कर चुप करा दिया। यह लापरवाही नहीं, यह अपराध है। बच्चों की बात को अनसुना करना, खतरे को नजरअंदाज करना और व्यवस्था की असंवेदनशीलता — ये सब इस मौत के बराबर दोषी हैं।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ — देशभर में ऐसे सैकड़ों स्कूल, भवन, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी क्वार्टर मौजूद हैं, जहाँ लोग रोज़ मौत के साए में जीते हैं।

भ्रष्टाचार भी है बड़ा कारण

भवन निर्माण में होने वाला घटिया निर्माण कार्य, बजट का दुरुपयोग, ठेकेदार-अफसर गठजोड़ — ये सभी दुर्घटनाओं के कारण हैं। सरकारें सालाना करोड़ों रुपये 'मरम्मती कार्य' के नाम पर देती हैं, लेकिन वो राशि कहाँ जाती है, इसका रिकॉर्ड ज़्यादातर मामलों में फर्जीवाड़ा से भरा होता है।

सरकारी रिकॉर्ड कहता है — "मरम्मत हो गई", लेकिन ज़मीनी हकीकत कहती है — "छत में दरार आज भी है"।

क्या गरीबों की जान इतनी सस्ती है?

जब किसी मंत्री की गाड़ी सड़क में गड्ढे के कारण झटके खा जाए, तो दूसरे ही दिन सड़क की मरम्मत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर किसी गरीब की जान उसी गड्ढे में चली जाए — तो एक जांच कमेटी बना दी जाती है, मुआवज़ा की घोषणा हो जाती है, और फिर सब भूल जाते हैं।

क्या यही है सामाजिक न्याय? क्या यही है सुशासन?

एक अधिकारी की गलती पर यदि VIP की कोठी टूटे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब किसी स्कूल में बच्चा मरता है, तो सब 'प्राकृतिक आपदा' या 'दुर्घटना' कह कर नज़रें फेर लेते हैं। ये संवेदनहीनता नहीं, यह अक्षम्य पाप है।

कानून, जवाबदेही और ज़रूरत की मांग

अब समय आ गया है कि देश में 'भवन सुरक्षा कानून' (Building Safety Accountability Law) की स्थापना हो। इसमें निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य किए जाएं:

हर सरकारी भवन की वार्षिक तकनीकी जांच हो।

हर विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल की संरचनात्मक सेफ्टी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

जहाँ भी खतरा हो, उसे तुरंत खाली कर मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जाए।

निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदार, इंजीनियर, और स्वीकृति अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो।

दुर्घटना होने पर सिर्फ मुआवजा नहीं, बल्कि आपराधिक मामला दर्ज हो।

मीडिया और समाज की भूमिका

हमें इन हादसों को केवल 'एक और दुखद समाचार' मानकर भूल नहीं जाना चाहिए। यह हमारी नागरिक चेतना की परीक्षा है। मीडिया को भी चाहिए कि वह इन मुद्दों को तब तक उठाता रहे, जब तक सरकारें नीतिगत बदलाव के लिए मजबूर न हो जाएं।

सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, ताकि "मौत के घरों में पलने वाली ज़िंदगियाँ" बचाई जा सकें।

सिस्टम को झकझोरने की ज़रूरत है

जब तक इस देश में गरीब की जान की क़ीमत केवल 5 लाख के मुआवज़े में आँकी जाती रहेगी, तब तक छतें गिरती रहेंगी, दीवारें ढहती रहेंगी, और सपने मरते रहेंगे।

लेकिन अब बहुत हो गया।

हमें पूछना होगा —

क्यों सिर्फ़ गरीबों के घर, स्कूल और अस्पताल ही गिरते हैं ?

क्या मंत्री, अधिकारी और संपन्न वर्ग के भवनों के लिए ही शासन सजग है ?

क्या शिक्षा का मंदिर अब बच्चों की समाधि बनते रहेंगे ?

अब वक्त है कि हम आवाज़ उठाएं — "हमें सुरक्षित भवन चाहिए, दिखावटी घोषणाएं नहीं।"

शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं के सुसाइड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त !

देश में छात्रों की खुदकुशी (सुसाइड) बहुत ही चिंताजनक है ।इस संदर्भ में हाल ही में हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दरअसल, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी और आईआईटी खड़गपुर में छात्रों की आत्महत्या के मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं ।पाठकों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी, खड़गपुर से पूछा कि छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ? और संस्थान क्या कर रहा है ? सुप्रीम कोर्ट ने शारदा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की पुलिस को चार हफ़्तों में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया ।सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि- कॉलेज के छात्रों ने पिता को बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है ? मैनेजमेंट ने क्यों नहीं बताया ? मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया ? क्या पुलिस और अभिभावकों को सूचित करना मैनेजमेंट का कर्तव्य नहीं है ? बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का छात्रों की आत्महत्या पर सख्त होना सही ही है, क्यों कि प्रबंधन, प्रशासन लापरवाही का परिचय दे रहे हैं और छात्रों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य, उनकी समस्याओं, सुरक्षा की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में, छात्रों की सुरक्षा, खासकर उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, संस्थानों की पहली नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य होना चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 15 अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने कहा कि ये दिशा-निर्देश तब तक लागू और बाध्यकारी रहेंगे, जब तक इस विषय में कोई कानून या नियम नहीं बन जाता। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि सभी शैक्षणिक संस्थान छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक समान नीति को अपनाएं और इसे लागू करें। वास्तव में, यह गंभीर चिंता का एवं संवेदनशील विषय है कि आज देशभर में अनेक संस्थान छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए न तो कोई नीतियां ही बनातें हैं और न ही इन्हें ठीक प्रकार से लागू ही करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों यह चाहिए कि वे छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक समान नीति बनाएं, उस नीति की समय-समय पर समीक्षा करें, उसे अद्यतन करें, इसे संस्थान की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक एवं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। छात्र-छात्राओं की अधिक संख्या वाले संस्थानों को यह चाहिए कि वे अपने यहां प्रशिक्षित काउंसलर(ट्रेंड काउंसलर) , मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर की नियुक्ति अनिवार्य करें ताकि बच्चों की समय-समय पर काउंसलिंग की जा सके और उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके। छात्र-छात्राओं की कम संख्या वाले संस्थानों में रिलायबल(भरोसेमंद) तथा ट्रेंड आउटर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट(प्रशिक्षित बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ) से औपचारिक रूप से सहयोग लिया जा सकता है और छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सकती है ।सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों से कहा है कि वे छात्रों को पढ़ाई के प्रदर्शन(मेरिट के आधार पर) के आधार पर बैच में न बांटने की बात कही है, क्यों कि ऐसा करने से छात्रों में शर्मिंदगी और मानसिक दबाव (मेंटल स्ट्रेस) पैदा होता है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यहां कार्यरत सभी स्टाफ (जैसे कि शिक्षण, गैर-शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ) सदस्यों को वंचित और हाशिये पर खड़े छात्रों के साथ संवेदनशील, समावेशी और भेदभाव रहित व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित हों ।सभी शिक्षण संस्थानों में यौन शोषण, उत्पीड़न, रैगिंग और जाति, वर्ग, लिंग, यौन रुझान, दिव्यांगता, धर्म या जातीयता के आधार पर होने वाली बदसलूकी की शिकायतों के लिए एक मजबूत, गोपनीय और सुलभ शिकायत व निवारण तंत्र बनाया जाना आवश्यक है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक आंतरिक समिति(इंटरनल कमेटी) भी संस्थानों में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी साफ कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा, खासकर उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, संस्थानों की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसी मामले में समय पर या पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई और इससे छात्र आत्महानि या आत्महत्या जैसा कदम उठाता है, तो यह संस्थान की लापरवाही मानी जाएगी और प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल, कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में कोटा, जयपुर, सीकर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जैसी सीरीज में अनेक कोचिंग संस्थान मौजूद हैं, जहां हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं नीट, बैंकिंग, आइआइटी जेईई मेन्स और एडवांस के साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं ।इन कोचिंग संस्थानों में छात्र-छात्राओं की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक और जरूरी है, क्यों कि कोचिंग संस्थानों में तैयारी करते समय घर से दूर रहने की स्थिति में इन छात्र-छात्राओं को अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पढ़ाई का अच्छा खासा दबाव छात्र-छात्राओं पर रहता है ।ऐसे में जरुरत इस बात की है कि इन कोचिंग संस्थानों में छात्र-छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और रोकथाम के विशेष उपाय लागू किए जाएं। प्रायः यह देखा गया है कि इन सीटीज में छात्रों की आत्महत्या के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए इन्हें खास ध्यान देने की जरूरत है। कहना ग़लत नहीं होगा कि कोटा में तो सुसाइड के आंकड़े बहुत ही डरावने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 तक ही 10 कोचिंग छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। पाठकों को बताता चलूं कि साल 2024 में कोटा से 17 छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले ही कोटा में आत्महत्याओं के मामलों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी और सवाल करते हुए यह पूछा था कि सिर्फ कोटा में ही आत्महत्या के मामले क्यों हो रहे हैं ? राजस्थान के कोटा ही नहीं सीकर से भी सुसाइड के मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार जुलाई 2025 में ही नीट के एक स्टूडेंट ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसने 9 जुलाई 2025 को ही सीकर की एक कोचिंग में दाखिला लिया था और मात्र एक दिन ही कोचिंग गया था। अन्य सीटीज में भी हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बहरहाल , हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो 15 अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ये दिशा-निर्देश देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे, चाहे वे सरकारी हों या निजी, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान, रेजिडेंशियल एकेडमी या छात्रावास उनकी मान्यता या संबद्धता चाहे जो भी हो। पाठकों को बताता चलूं कि किसी भी कारण से तनावग्रस्त छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों, अनिवार्य काउंसलिंग , शिकायत निवारण तंत्र और नियामक ढांचों को अनिवार्य बनाने हेतु ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने इस संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है। इन नियमों के तहत सभी निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण, छात्रों की सुरक्षा से जुड़े मानदंड और शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य किए जाने की बातें कहीं गईं हैं, यह काबिले-तारीफ है। इन संस्थानों को छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था का पालन भी सुनिश्चित करना होगा ।इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसमें सरकार को यह बताना होगा कि दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, राज्य सरकारों के साथ किस तरह समन्वय किया गया है, कोचिंग संस्थानों से जुड़े नियम बनाने की क्या स्थिति है और निगरानी की क्या व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हलफनामे में सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट और सिफारिशें कब तक पूरी होंगी ? कहना ग़लत नहीं होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर भारत के शैक्षणिक ढांचे में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, लेकिन अब देखना यह है कि केंद्र सरकार, विभिन्न राज्यों और विभिन्न संस्थानों द्वारा इसे कितनी गंभीरता से और कब लागू किया जाता है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि आज हमारे देश में छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं चिंताजनक स्थिति पर पहुंच चुकी हैं ।एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल करीब 13,044 छात्र आत्महत्या करते हैं ।रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश भर में कुल 1 लाख 70 हजार 924 लोगों ने आत्महत्या की। साल 2022 में 70,924 में से 13,044 तो छात्र ही थे, जबकि बीस साल पहले 2001 में स्टूडेंट्स की मौत के आंकड़े 5,425 थे। मतलब यह है इक्कीस साल में यह आंकड़ा काफी बढ़ गया। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि देश में आत्महत्या करने वाले कुल लोगों में छात्रों की संख्या 7.6 फीसदी है ? इसके बाद के वर्षों के आधिकारिक आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन आशंका है कि यह संख्या बढ़ी हुई हो। कहना ग़लत नहीं होगा कि छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारण शैक्षणिक और सामाजिक-पारिवारिक तनाव व दवाब के साथ-साथ कॉलेजों या संस्थाओं से मदद ना मिलना और जागरूकता का अभाव है। बच्चों के बीच पढ़ाई में लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा, अंकों की होड़ और बच्चों से माता-पिता/अभिभावकों की बहुत सी अपेक्षाएं भी सुसाइड का प्रमुख कारण बन रहीं हैं ।यह विडंबना ही है कि छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर न तो परिवार(माता-पिता , अभिभावक) ही गंभीर होते हैं, न ही शिक्षण संस्थान। कहना ग़लत नहीं होगा कि हताश, तनावग्रस्त व अवसाद वालों को मनोवैज्ञानिक मदद के सहारे काफी हद तक उबारा जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी) करते आए हैं। पाठकों को बताता चलूं कि हर साल शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के सवालों के जवाब देते हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, करियर और दूसरे विषयों पर भी बात की जाती है, लेकिन बावजूद इसके भी धरातल स्तर पर कोचिंग संस्थान कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तो यह विडंबना ही कही जा सकती है। सारा काम सरकार नहीं कर सकती है। जिम्मेदारी सरकार के साथ ही साथ हमारी स्वयं की, अधिकारियों की, प्रशासन की तथा संस्थानों की भी है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग, शिकायत निवारण और संस्थागत जवाबदेही पर हम सभी को सामूहिकता के साथ काम करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया जाना अदालत की सर्वोच्च संवेदनशीलता का द्योतक है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

रियायती तेल या अमेरिकी टैरिफ ? भारत के सामने आर्थिक धर्मसंकट

[रूसी हथियारों से अमेरिकी टैक्स तक : भारत के लिए दोधारी चुनौती]

भारत और रूस का रिश्ता मात्र साझेदारी नहीं, बल्कि विश्वास और सामरिक एकजुटता का अटूट बंधन है, जो दशकों की कठिन कसौटियों पर खरा उतरा है। यह रिश्ता न केवल हथियारों और तेल के व्यापार तक सीमित है, बल्कि भारत की रक्षा ताकत, ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन का मजबूत आधार है। लेकिन अब यह बंधन एक अभूतपूर्व तूफान का सामना कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कठोर चेतावनी ने भारत को दोराहे पर ला खड़ा किया है—रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद की क़ीमतर चुकाने की धमकी दी गई है। एक अगस्त से भारत के हर निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूस से सैन्य खरीद के लिए अतिरिक्त रूपेनल्टीर का ऐलान हुआ है। अमेरिका का तर्क है कि भारत का रूस के साथ व्यापार यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यह धमकी ऐसे नाजुक समय में आई है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते की बातचीत महीनों से अधर में लटकी हुई है। सवाल यह नहीं कि भारत क्या कदम उठाएगा; सवाल यह है कि क्या भारत इस बाहरी दबाव के सामने झुकेगा, या अपने राष्ट्रीय हितों को ढाल बनाकर रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को अडिग रखेगा ?

भारत की सैन्य शक्ति का आधार रूस से प्राप्त तकनीक और उपकरणों पर टिका है। भारतीय सेना के 60 से 70 प्रतिशत उपकरण—जैसे टैंक, फाइटर जेट, पनडुब्बियाँ और मिसाइल सिस्टम—सोवियत या रूसी मूल के हैं। 2023 के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के आँकड़ों के अनुसार, भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है। मिग-29, सुखोई-30 एमकेआई और टी-90 टैंक जैसे उपकरण भारत की रक्षा रीढ़ की हड्डी हैं। इनका रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और उन्नयन रूस के सहयोग के बिना असंभव है। भले ही भारत रूस से नए उपकरण खरीदना बंद कर दे, अगले दशक तक मौजूदा उपकरणों को चालू रखने के लिए रूसी सहायता अनिवार्य रहेगी। यह निर्भरता केवल तकनीकी नहीं, बल्कि भारत की सामरिक संप्रभुता का आधार है।

रूस भारत के लिए केवल रक्षा साझेदार नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का भी मज़बूत स्तंभ है। 2024 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया, जो उसकी कुल तेल खपत का 35 प्रतिशत है। रियायती दरों पर उपलब्ध यह तेल भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाता है। यदि भारत रूस से तेल आयात बंद करता है, तो उसे खाड़ी देशों से महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा और आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती होगा।

इस धमकी का भू-राजनीतिक आयाम और भी जटिल है। रूस से दूरी भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हो सकती है। रूस के कुल तेल निर्यात का 47 प्रतिशत पहले ही चीन को जाता है, और यह हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यदि भारत रूस से पीछे हटता है, तो रूस की चीन पर निर्भरता और गहरी होगी, जो भारत के हितों के लिए अस्वीकार्य है। भारत पहले ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती साझेदारी से जूझ रहा है। रूस और पाकिस्तान के बीच हाल के वर्षों में बढ़ते सैन्य और आर्थिक संबंध, जैसे 2016 से शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत के लिए चिंता का विषय हैं। यदि रूस चीन और पाकिस्तान के और करीब जाता है, तो भारत का क्षेत्रीय संतुलन खतरे में पड़ सकता है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम भारत की सुरक्षा और सामरिक स्थिरता के लिए विनाशकारी होंगे।

भारत और रूस का रिश्ता केवल हथियारों और तेल तक सीमित नहीं, बल्कि यह रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का एक गहरा बंधन है। रूस चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तरी-दक्षिणी परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भारत का अहम साझेदार है। चाबहार बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापारिक और सामरिक पहुँच प्रदान करता है, जो उसकी भू-राजनीतिक रणनीति का आधार है। यदि भारत रूस से दूरी बनाता है, तो ये परियोजनाएँ जोखिम में पड़ सकती हैं, जिससे न केवल भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं को गहरा झटका लगेगा, बल्कि क्षेत्र में उसका प्रभाव और प्रभुत्व भी कमजोर होगा।

भारत और अमेरिका के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत में अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास रहा है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाए। इसके विपरीत, रूस ने न केवल भारत का साथ दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में उसके पक्ष में वीटो शक्ति का उपयोग किया। रूस की नीतियों में 2000 के बाद से उल्लेखनीय निरंतरता रही है, जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ नीतियाँ अक्सर बदलती रहती हैं। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अचानक वापसी इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारत ने वहाँ 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया था, लेकिन तालिबान के सत्ता में लौटने से उसकी परियोजनाएँ संकट में पड़ गईं। यह घटना भारत में इस धारणा को और पुष्ट करती है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा में विश्वसनीय नहीं है।

अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भारतीय सेना में एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। भारत ने 2010 के बाद अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, चिनूक हैवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर और सी-17 ट्रांसपोर्ट विमान जैसे उन्नत उपकरण खरीदे हैं, लेकिन ये अभी भी उसकी सैन्य क्षमता का सीमित हिस्सा हैं। इन उपकरणों को पूरी तरह अपनाने, प्रशिक्षण और रखरखाव में भारी लागत और लंबा समय लगता है। रूसी उपकरणों को अमेरिकी उपकरणों से बदलना न केवल आर्थिक रूप से बोझिल है, बल्कि यह एक दशकों लंबी रणनीतिक प्रक्रिया है। यह बदलाव आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से व्यवहार्य नहीं है, जिसके चलते भारत को अपनी रक्षा नीतियों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

इस धमकी का आर्थिक आयाम अत्यंत गंभीर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहाँ 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर को पार कर गया। 25 प्रतिशत टैरिफ जैसे कदम भारत के आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्रों को गहरी चोट पहुँचाएँगे। हालाँकि, रूस से दूरी का नुकसान इससे कहीं अधिक विनाशकारी होगा। रूस वह विश्वसनीय साझेदार रहा है, जिसने भारत को हर संकट में अडिग समर्थन दिया। यह रिश्ता केवल व्यापारिक गणनाओं का नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और रणनीतिक एकजुटता का प्रतीक है, जिसे आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता।

इस निर्णायक मोड़ पर भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। रूस के साथ साझेदारी न केवल भारत की रक्षा और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अपरिहार्य है, बल्कि क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। यदि भारत रूस से दूरी बनाता है, तो यह रूस को चीन और पाकिस्तान के करीब धकेल सकता है—एक ऐसा परिदृश्य जो भारत के लिए भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से विनाशकारी होगा। भारत को इस दबाव का जवाब कूटनीतिक कुशलता और अटल दृढ़ता के साथ देना होगा। न तो अपनी रक्षा क्षमताओं को कमजोर करना है, न ही आर्थिक हितों को खतरे में डालना है। यह समय भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को और सशक्त करने का है, जिसमें वह किसी भी बाहरी दबाव के सामने न झुके और अपने हितों को अडिग रखे। भारत का इतिहास यही सिखाता है—विश्वास, संतुलन और दृढ़ता के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

'शोनार बांग्ला' कैसे बन रहा उद्योग-धंधों का कब्रिस्तान

रामस्वरूप रावतसरे

पश्चिम बंगाल से बीते डेढ़ दशक में 6 हजार से अधिक कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा है। इनमें से 2 हजार से अधिक कंपनियाँ बीते 5 वर्षों में राज्य छोड़ कर गई हैं। यह भी सामने आया है कि इस दौरान यह कंपनियाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को गई हैं। पश्चिम बंगाल से उद्योग धंधों का यह पलायन तृणमूल कॉन्ग्रेस (टीएमसी) के राज में हुआ है। पश्चिम बंगाल में जहाँ एक ओर कंपनियाँ राज्य छोड़ कर जा रही हैं, वहीं नए निवेश भी नाममात्र को हो रहे हैं। देश के चौथे सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के लिए यह स्थिति गंभीर और चिंताजनक है।

यह आँकड़े भले ही चौंकाने वाले हों, लेकिन उद्योग-धंधों का पलायन और पश्चिम बंगाल का पुराना रिश्ता है। देश के बड़े कारोबारी घरानों के अपना मुख्यालय शिफ्ट करने से बड़े ब्रांड्स के फैक्ट्री बंद करने तक यही हाल बीते कई सालों से है। इसमें एक कारण ममता बनर्जी सरकार का उद्योग विरोधी रुख और राज्य की खस्ताहाल कानून-व्यवस्था बताया जा रहा है। कभी एशिया की बड़ी औद्योगिक ताकतों में से एक गिने जाने वाले कोलकाता के अवसान की यह पटकथा ममता बनर्जी के राज से पहले वामपंथियों ने लिख दी थी लेकिन ममता बनर्जी ने इस पटकथा को अंतिम रूप दिया है और उद्योग-धंधों में इजाफा करने के बजाय उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की कसर पूरी कर दी है।

राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल पर एक प्रश्न पूछा। उनके उत्तर में केन्द्र सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2024-25 के बीच पश्चिम बंगाल से 6688 कंपनियाँ राज्य छोड़ कर गई हैं। मंत्रलाय के उत्तर के अनुसार इनमें से एक तिहाई यानी 2200 से अधिक कंपनियाँ वर्ष 2019 के बाद से राज्य छोड़ कर गई हैं। यह ट्रेंड 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से लगातार जारी है। मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6688 कंपनियों में से 110 कंपनियाँ ऐसी थीं जो शेयर बाजार में भी सूचीबद्ध थीं। मंत्रालय का डाटा बताता है कि 2017-18 के दौरान सबसे अधिक 1027 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल छोड़ा है। 2015-16 और और 2016-17 के दौरान क्रमशः 869 और 918 कंपनियों ने पश्चिम बंगाल से कारोबार समेटा है।

कॉर्पोरेट मंत्रालय के उत्तर के अनुसार पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली कंपनियाँ दूसरे राज्यों में जा रही हैं। इनका पलायन ऐसे राज्यों में हो रहा है, जहाँ उद्योग को लेकर नीतियाँ सरल हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2011-25 के बीच पश्चिम बंगाल छोड़ कर सर्वाधिक कंपनियाँ महाराष्ट्र गईं हैं। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश उनकी पसंदीदा लोकेशन में शामिल हुए हैं। कॉर्पोरेट मंत्रालय का उत्तर बताता है कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 1300 से अधिक कंपनियाँ 2011-25 के बीच महाराष्ट्र गईं हैं। वहीं 1297 ने दिल्ली को चुना है। इसके अलावा 879 कंपनियाँ पश्चिम बंगाल छोड़ कर उत्तर प्रदेश में गई हैं।

छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान भी 1000 से अधिक कंपनियाँ पश्चिम बंगाल से छीनने में सफल रहे हैं हालाँकि, इस सबका तृणमूल सरकार पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। वह उद्योग धंधों को राज्य में लाने के बजाय उन्हें और राज्य निकाला देने पर तुली दिखाई पड़ती है।

जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में दशकों से व्यापार करने वाली कंपनियाँ एक ओर राज्य छोड़ रही हैं तो वहीं हाल ही में बनर्जी की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे यह पलायन और तेज हो सकता है। अप्रैल, 2025 में राज्य की ममता सरकार ने उद्योगों को लाभ पहुँचाने वाली सभी सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। उद्योग-धंधों को लुभाने के लिए 1993 से लेकर 2021 तक बनाई गई सभी नीतियाँ एक झटके में राज्य सरकार ने खत्म कर दी थीं। इसका असर यह होगा कि राज्य में कोई भी उद्योग स्थापित करने पर किसी कारोबारी को कोई लाभ नहीं मिलेगा चाहे वह जमीन से जुड़ा हो, बिजली से जुड़ा हो या फिर अन्य किसी एंगल से।

एक रिपोर्ट बताती है कि ममता सरकार ने उद्योग धंधों को यह फायदे देने इसलिए बंद किए थे ताकि वह 'सामाजिक कार्यों' के लिए और पैसा सरकारी खजाने से मुक्त कर सके। इसका अर्थ है कि ममता सरकार उद्योग धंधों को बंद करके लोगों को और खुद पर निर्भर करना चाहती है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के इस कदम से कई सीमेंट कंपनियाँ बड़ा झटका झेलेंगी। इनमें डालमिया जैसे देश के पुराने और विशाल कारोबारी घराने भी शामिल हैं। यह नुकसान 500 करोड़ तक का बताया गया था। उद्योग धंधों को कोई भी लाभ ना देने का यह कदम पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे समय में उठाया है जब बाकी राज्य उनके लिए बाँहें खोल कर खड़े हैं। कहीं 1 रूपये में जमीन दी जा रही है तो कहीं पूरे-पूरे नए शहर बनाए जा रहे हैं ताकि उद्योग-धंधे उनके यहाँ आ सकें।

पश्चिम बंगाल में पुरानी कंपनियाँ तो बाहर जा रही हैं, नया निवेश भी सिर्फ घोषणाओं और कागजों में ही आ रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि जनवरी-नवम्बर 2024 में पश्चिम बंगाल में 39 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए थे। उन्होंने दावा किया था कि यह देश में तीसरा सर्वाधिक है। केंद्र सरकार के एक और विभाग की एक रिपोर्ट इस दावे की सच्चाई खोलती है। भले ही राज्य में बड़े-बड़े निवेश के वादे किए गए हो लेकिन असल में यह वादों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। डीपीआईआईटी की आईईएम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2024 में नवम्बर माह तक 3735 करोड़ के निवेश ही हुए थे जबकि वादा कहीं अधिक था। पश्चिम बंगाल औद्योगिक निवेश के मामले में भी बाक़ी राज्यों के सामने कहीं नहीं ठहरता। यही रिपोर्ट बताती है कि 2020-24 के बीच जहाँ उत्तर प्रदेश में 71 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है तो वहीं इस दौरान पश्चिम बंगाल मात्र 15 हजार करोड़ का ही निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा। निवेश आकर्षित करने के मामले में वह झारखंड तक से पीछे बताया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी ही रहा है। 2024 में राज्य में ब्रिटानिया ने अपनी दशकों पुरानी बिस्किट फैक्ट्री को ताला लगा दिया था। यह फैक्ट्री कोलकाता के पास स्थापित थी। इसी तरह कई जूट मिलें भी राज्य में बंद हो चुकी हैं, या फिर अंतिम साँसे गिन रही हैं। ब्रांड्स के बंगाल छोड़ने का सिलसिला कोई नया नहीं है। असल में ममता बनर्जी के राजनैतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ यही एक कारण रहा है। 2008 में राज्य को टाटा मोटर्स ने छोड़ा था, वह सिंगूर में नैनो की फैक्ट्री लगा रहा था लेकिन ममता बनर्जी के लगातार विरोध के चलते उसे बनी-बनाई फैक्ट्री उखाड़नी पड़ी और गुजरात भागना पड़ा। ममता बनर्जी इसी सिंगूर के आंदोलन के बाद ही राज्य में बड़ी जीत हासिल कर पाईं और सत्ता में तीन दशक से अधिक से जमे बैठे कम्युनिस्टों की जगह ली। हालाँकि, जिस नेता के सत्ता में आने का कारण ही किसी उद्योग का विरोध रहा हो, उससे उद्योग समर्थक नीति की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

जानकारों की माने तो इसी बंगाल में कभी आदित्य बिरला को उनकी गाड़ी से खींच कर सड़क पर पीटा गया था और नंगा कर बेईज्जत किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना कारोबार समेट लिया। यही हाल और भी उद्योग घरानों का हुआ बताया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल से उद्योग धंधों का पलायन राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल देश में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है लेकिन इसका देश के औद्योगिक आउटपुट में मात्र 3.5 प्रतिशत हिस्सा है। इसमें पीछे होने के चलते राज्य में भारी बेरोजगारी की समस्या है। अवैध घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल में आना इस समस्या को और भीषण बनाता है। राज्य में आए दिन होते दंगे और बहुसंख्यक आबादी पर हमले भी घटते विश्वास का कारण बने हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था की दयनीय स्थिति के चलते कोई बड़ी कम्पनी निवेश नहीं करना चाहती।

जानकारों के अनुसार यही कारण है कि 1960 के दशक में जिस पश्चिम बंगाल का देश की जीडीपी में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान था, वह अब मात्र 5 प्रतिशत तक आकर टिक गया है। उससे छोटे राज्य उससे आगे निकलने वाले हैं। यदि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का यही रवैया रहा तो इससे बाकी देश भी प्रभावित होगा और उसकी धीमी आर्थिक विकास की गति देश को पीछे खींचेगी।

1 से 7 अगस्त: विश्व स्तनपान सप्ताह

स्तनपान सप्ताह: संकोच तोड़ने और सम्मान

[हर मां का अधिकार, हर शिशु का जीवनाधिकार – स्तनपान]

स्तनपान केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मां और शिशु के बीच एक अटूट बंधन, स्वास्थ्य का आधार और भावनात्मक जुड़ाव का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह इस महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्तनपान के लाभों को प्रचारित करना, भ्रांतियों को दूर करना और समाज के हर वर्ग को इसके प्रति जागरूक करना है। यह सप्ताह केवल मां और शिशु तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार, समुदाय, कार्यस्थल और नीति-निर्माताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार, जन्म के पहले घंटे में शिशु को मां का पहला दूध, यानी कोलोस्ट्रम, देना अनिवार्य है। यह गाढ़ा, पीला दूध शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला अमृत है, जिसमें एंटीबॉडीज और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि पहले छह महीने तक शिशु को केवल मां का दूध दिया जाए और फिर दो साल तक ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जाए। यह शिशु के शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

स्तनपान शिशु को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है और कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा देता है। शोध बताते हैं कि मां के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज शिशु को डायरिया, निमोनिया, श्वसन संक्रमण और यहां तक कि दीर्घकालिक बीमारियों जैसे मधुमेह और मोटापे से बचाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, स्तनपान करने वाले बच्चों का आईक्यू औसतन 3-7 अंक अधिक होता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, यदि वैश्विक स्तर पर छह महीने तक विशेष स्तनपान को बढ़ावा दिया जाए, तो हर साल 8 लाख से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा, स्तनपान शिशु में एलर्जी, अस्थमा और आंतों के रोगों के जोखिम को भी कम करता है।

मां के लिए भी स्तनपान अनेक लाभकारी है। यह प्रसवोत्तर रक्तस्राव को नियंत्रित करने और गर्भाशय को सामान्य स्थिति में लाने में मदद करता है। शोधों के अनुसार, स्तनपान करने वाली माताओं में स्तन कैंसर का जोखिम 25% तक और डिम्बग्रंथि कैंसर का जोखिम 30% तक कम हो सकता है। इसके अलावा, यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों से भी बचाव करता है। स्तनपान एक प्राकृतिक गर्भनिरोधक के रूप में भी कार्य करता है, जिसे लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कहा जाता है, हालांकि यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। भावनात्मक दृष्टिकोण से, स्तनपान मां और शिशु के बीच गहरा जुड़ाव बनाता है, जो मां के मानसिक स्वास्थ्य और शिशु की भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देता है।

विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल एक नई थीम के साथ आता है, जो वैश्विक आवश्यकताओं और चुनौतियों को उजागर करता है। वर्ष 2025 की थीम, "स्तनपान के लिए समावेशी समाज का निर्माण: सभी के लिए समान अवसर," इस बात पर बल देती है कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। आधुनिक युग में, जहां कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, कार्यस्थलों पर स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है। इसमें निजी और स्वच्छ स्तनपान कक्ष, दूध संग्रह की सुविधाएं, और पर्याप्त ब्रेक का प्रावधान शामिल है। भारत में मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश एक सकारात्मक कदम है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऐसी सुविधाओं की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में केवल 30% कार्यस्थलों पर स्तनपान के लिए उपयुक्त सुविधाएं हैं, जो इस दिशा में समावेशी और समान प्रयासों की जरूरत को रेखांकित करता है।

सामाजिक दृष्टिकोण से, स्तनपान को लेकर कई भ्रांतियां और संकोच अभी भी मौजूद हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराना कई महिलाओं के लिए असहजता और सामाजिक दबाव का कारण बनता है। कुछ समाजों में इसे अशोभनीय माना जाता है, जो एक गलत धारणा है। विश्व स्तनपान सप्ताह का एक प्रमुख उद्देश्य इन रूढ़ियों को तोड़ना और स्तनपान को एक सामान्य, गरिमामय और प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता अभियान, जैसे टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर सूचनात्मक विज्ञापन, माताओं की प्रेरक कहानियां और सामुदायिक स्तर पर चर्चाएं महत्वपूर्ण हैं।

स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता का प्रसार महत्वपूर्ण है। किशोरियों और युवतियों को स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से मातृत्व और स्तनपान के बारे में जानकारी देना जरूरी है। इससे वे मातृत्व के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सकती हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेवाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर में अभी भी असमानता है। उदाहरण के लिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार, भारत में केवल 64% शिशुओं को जन्म के पहले घंटे में स्तनपान कराया जाता है, जो वैश्विक मानकों से कम है।

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर स्तनपान के समर्थन में ठोस नीतियां और अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यस्थलों पर सख्त दिशानिर्देश, स्वास्थ्य केंद्रों में परामर्श सेवाएं, और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। भारत में "मां" (एमएए - मदर्स एबसोल्यूट अफेक्शन) कार्यक्रम एक सकारात्मक पहल है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है और माताओं को स्तनपान के लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवनशैली इस प्रक्रिया में बाधा बनती है।

स्तनपान केवल एक व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण तभी संभव है, जब मां और शिशु को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समर्थन मिले। विश्व स्तनपान सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हर मां को सम्मान के साथ, बिना किसी संकोच या भय के, कहीं भी और कभी भी स्तनपान कराने का अधिकार है। यह केवल एक सप्ताह का आयोजन नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नीति, शिक्षा, व्यवहार और सहानुभूति का समावेश होना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर स्तनपान के अनुकूल वातावरण बनाएं, तो यह न केवल शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी देगा, बल्कि एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह सप्ताह हमें प्रेरित करता है कि हम इस दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाएं, जो भविष्य में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",
बड़वानी (मप्र)

मोक्ष सप्तमी पर महिला मण्डल ने लाडू निर्माण किया

हरि सिहं चौहान

मोक्ष सप्तमी पर 23 वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर दिगम्बर जैन मंदिरों में पूजा-अर्चना कर बड़ी धूमधाम से यहां पर्व जैन धर्मावलंबी ने मनाया इस अवसर पर मंदिर जी में अलग अलग कार्यक्रम रखें गये। दिगंबर जैन मंदिर वैभव नगर इन्दौर में लाडू निर्माण हेतु महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर महिला मण्डल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिसमें उन्हें वैभव नगर मंदिर समिति ने पुरस्कृत किया गया।

मुकुट सप्तमी पर मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया।

'सास्वततीर्थ सम्मेद शिखर जी के परम पुनीत स्वर्ण भद्र कूट से मोक्ष पधारे भगवान श्री पारसनाथ स्वामी के निर्वाण महोत्सव,मोक्ष सप्तमी पर प्राचीनतम जिनालय श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जबरी बाग नसिया जी इन्दौर में विभिन्न कार्यक्रम के मध्यम से मोक्ष कल्याण महामहोत्सव मनाया गया। जिसमें शांति धारा , कलशाभिषेक व निर्माण लाडू भी चढ़ायें गये । इस अवसर पर सभी समाजजन शमिल हुए।

पुरी-राउरकेला वंदे भारत के कोच दोगुने

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर : पुरी और राउरकेला के बीच चलने वाली तेज़ और आरामदायक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में डिब्बों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। पहले 8 डिब्बों वाली यह ट्रेन आगामी 7 अगस्त से 16 डिब्बों के साथ चलेगी। डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए इसमें आठ नए एसी चेयर कार डिब्बे जोड़े गए हैं।जिससे यात्रियों को अब लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना नहीं करना पड़ेगा। डिब्बों की संख्या बढ़ने के बाद, इसमें 12 एसी चेयर कार कोच, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच और 2 क्रू और एसी चेयर कार कोच होंगे।

पुरी-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से ही काफी मांग रही है। यह ट्रेन वर्तमान में 110% से अधिक क्षमता पर चल रही है। जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। पुरी से राउरकेला के लिए मांग 112.76% है, जबकि राउरकेला से पुरी के लिए मांग है। पूर्वी तट रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बढ़ी हुई मांग की समीक्षा के बाद, पुरी-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में और डिब्बे जोड़े गए हैं। डिब्बों की संख्या बढ़ने से अधिक यात्रियों को लाभ होगा। यह ट्रेन लगभग 7.5 घंटे में 505 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलती है। यह पुरी और राउरकेला के बीच नौ स्टेशनों पर रुकती है। यह खोरधा रोड जंक्शन, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, तालचेर रोड, अंगुल, रेडाखोल, संबलपुर सिटी और झारसुगुड़ा जंक्शन पर रुकती है।

बिजेड़ी का भाजपा के प्रति छुपा प्रेम एक बार फिर सामने आ गया है

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : बीजेडी का झगड़ा और भाजपा के प्रति छुपा प्रेम एक बार फिर सामने आ गया है। आप सभी जानते ही हैं कि संसद इस समय ऑपरेशन सिंधु को लेकर व्यस्त है। और इसी मुद्दे पर बीजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंधु को लेकर जहाँ 7 में से 5 राज्यसभा सांसदों ने संसद में सेना की तारीफ़ की, वहीं खबर है कि 2 बीजेडी सांसदों ने इस चर्चा से खुद को अलग कर लिया है।परिणामस्वरूप, बीजद सांसद सामने आ गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीजद को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कुल 28 मिनट का समय दिया गया था। जिसमें से पार्टी के 5 राज्यसभा सांसदों ने इसमें भाग लिया। सुभाशीष खुंटिया ने 5 मिनट, मानस मंगराज ने 4 मिनट, सुलता देव ने 8 मिनट, सस्मित पात्रा ने 7 मिनट और निरंजन त्रिकया ने 4 मिनट चर्चा में भाग लिया। हालाँकि, खबर है कि पार्टी ने पार्टी के अन्य दो सांसदों, देबाशीष सामंत्रे और मुन्ना खान को इस चर्चा में भाग लेने का मौका नहीं दिया। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बीजद के इन दोनों सांसदों को चर्चा में भाग लेने का मौका क्यों नहीं दिया गया? या फिर दोनों सांसदों ने जानबूझकर चर्चा में भाग नहीं लिया, जिस पर अब बहस छिड़ गई है।

वक्फ विधेयक पर भी विवाद हुआ था । अप्रैल में जब संसद में वक्फ विधेयक पर चर्चा और मतदान हुआ था, तब सबकी नज़र थी। उस समय बीजद विधेयक का समर्थन कर रहा था या विरोध... यह तय होना बाकी था। लेकिन पार्टी ने समर्थन या विरोध का फ़ैसला सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया था। नतीजतन, पार्टी के पाँच सांसदों ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। इस दौरान बीजद सांसद मुन्ना खान ने वक्फ विधेयक का खुलकर विरोध किया, जबकि देबाशीष सामंतराय मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जिन सांसदों ने वक्फ विधेयक के पक्ष में मतदान किया था, उन्हीं बीजद सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया है। और अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की मोदी सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया है।बीजद का नरम रुख, क्या यह भाजपा के प्रति प्रेम है?

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल बीजद सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने संसद में केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख दिखाया। जब संसद में अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर तीखी भाषा में निशाना साध रहे थे, तब बीजद सांसदों ने सिर्फ़ सेना की तारीफ़ की और मोदी सरकार पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया। बीजद नेताओं ने सेना के साहस और बहादुरी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ओडिशा के 4.5 करोड़ ओडिया लोगों ने हमेशा सेना का समर्थन किया है, लेकिन इस सब के बीच, बीजद सांसद अन्य विपक्षी दलों की तरह भाजपा सरकार पर सवाल नहीं उठा सके। एक बात ध्यान में आती है कि इस बार बीजद ने संसद में न सिर्फ़ सेना की तारीफ़ की, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की मोदी सरकार के प्रति समर्थन भी जताया। लेकिन जब पार्टी राज्य में विपक्ष की सीट पर बैठी है और सच्चाई से कोसों दूर है, तो देखना होगा कि पार्टी का यह रुख़ पार्टी को कितना फ़ायदा पहुँचाता है और कितना नुकसान।

स्क्रीन का शिकंजा: ऑस्ट्रेलिया से सबक लेता भारत?

ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने का साहसिक फैसला लिया है। यह कदम बच्चों को ऑनलाइन दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। भारत जैसे देशों में, जहां डिजिटल लत तेजी से फैल रही है, वहां इस तरह की नीति बेहद जरूरी हो गई है। यह समय है कि भारत भी बच्चों के डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट कानून बनाए, अभिभावकों को जागरूक करे और बच्चों को स्क्रीन की लत से मुक्त करके संतुलित विकास की दिशा में कदम बढ़ाए।ऑस्ट्रेलिया के फैसले से दुनिया के देशों को सबक लेना चाहिए कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने का समय अब आ गया है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

"बचपन अब किताबों से नहीं, स्क्रीन की चमक से आकार ले रहा है।" यह वाक्य अब सिर्फ साहित्यिक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि हमारे समाज की वास्तविकता बन चुका है। मोबाइल, टैबलेट और इंटरनेट की पहुँच बच्चों तक इतनी सहज हो चुकी है कि चार साल का बच्चा भी यूट्यूब पर कार्टून देख सकता है और दस साल का बच्चा इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना जानता है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लिया गया फैसला न सिर्फ साहसिक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। ऑस्ट्रेलिया ने यह तय कर दिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह नीति 10 दिसंबर से लागू हो रही है, और इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्लेटफार्मों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफार्मों को 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है। अब यूट्यूब को भी इसी दायरे में शामिल किया गया है। यह दुनिया का पहला कानून है जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर इतनी स्पष्टता और कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है। नियमों के मुताबिक अगर कोई प्लेटफार्म 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवाएं देना जारी रखता है, तो उस पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि टेक कंपनियों को जवाबदेह बनाने की एक गंभीर कोशिश है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यह स्पष्ट कहा है कि माता-पिता को यह जानने का हक है कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और किसके प्रभाव में हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म पर जो सामग्री बच्चों के सामने आती है, वह कई बार हिंसा, लैंगिक पूर्वाग्रह, अपशब्दों और अमर्यादित व्यवहार से भरी होती है। इतना ही नहीं, बच्चों को लगातार विज्ञापन, ब्रांडेड कंटेंट और चकाचौंध वाली ज़िंदगी दिखाकर उनकी असल दुनिया से दूरी बढ़ाई जा रही है।

यूट्यूब का कहना है कि वह केवल एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म है और उसे सोशल मीडिया की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। यूट्यूब के प्रवक्ता का तर्क है कि 13 से 15 साल के लगभग तीन-चौथाई ऑस्ट्रेलियाई किशोर इसका उपयोग करते हैं और इसे शैक्षणिक, रचनात्मक व मनोरंजक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल उठता है कि क्या यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म बच्चों के लिए वाकई सुरक्षित हैं? क्या वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को केवल उपयुक्त और सकारात्मक सामग्री ही दिखाई जाए? वास्तविकता यह है कि अधिकतर टेक कंपनियाँ केवल व्यूज़, क्लिक और विज्ञापन राजस्व के लिए काम करती हैं, न कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए।

भारत जैसे देशों में यह मुद्दा और अधिक गंभीर हो जाता है। यहां इंटरनेट यूज़र्स की संख्या करोड़ों में है, जिनमें बड़ी संख्या किशोरों और स्कूली बच्चों की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 13 से 17 वर्ष के बच्चे हर दिन औसतन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। इतनी कम उम्र में जब बच्चों को किताबों, खेल और सामाजिक मेल-जोल में समय बिताना चाहिए, वे अपने कमरे में अकेले बैठकर स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इससे न सिर्फ उनकी आँखों और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक विकास भी बाधित होता है।

स्कूलों में शिक्षकों को अब इस बात की चिंता होती है कि विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रात भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। माता-पिता इस कशमकश में रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल दें या न दें, क्योंकि अगर वे न दें तो बच्चा पिछड़ने का डर जताता है, और दें तो स्क्रीन की लत लग जाती है। डिजिटल लत अब नशे की तरह फैल चुकी है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, एकाग्रता में गिरावट और रिश्तों से दूरी जैसी समस्याएँ अब आम हो चुकी हैं। कुछ बच्चे तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

भारत में अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर 13 साल की आयु सीमा तो तय है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। बच्चे गलत उम्र डालकर खाते बना लेते हैं और बिना किसी निगरानी के उनका इस्तेमाल करते हैं। माता-पिता की भूमिका भी संदिग्ध है — कुछ अभिभावक खुद ही बच्चों को स्क्रीन थमाकर व्यस्त कर लेते हैं, जबकि उन्हें मार्गदर्शक बनना चाहिए। इसके अलावा, भारत में स्कूल स्तर पर भी डिजिटल नैतिकता की शिक्षा का अभाव है। बच्चों को यह नहीं सिखाया जाता कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें, फर्जी समाचारों से कैसे बचें, या साइबर खतरों से कैसे सतर्क रहें।

समस्या सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जागरूकता की भी है। जब तक माता-पिता, शिक्षक और सरकारें मिलकर यह तय नहीं करेंगी कि बच्चों को किस तरह की डिजिटल दुनिया में प्रवेश करना है, तब तक कोई भी तकनीकी समाधान प्रभावी नहीं हो सकता। डिजिटल अनुशासन केवल कानून से नहीं, संस्कार और समझ से आता है।

ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इस मायने में प्रेरक है कि उसने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दी और टेक कंपनियों को चुनौती दी। भारत को भी अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यह समय है जब सरकार एक स्पष्ट और सख्त नीति बनाए कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और मनोरंजक प्लेटफार्म से दूर रखा जाएगा। साथ ही, कंटेंट फिल्टरिंग, स्क्रीन टाइम लिमिट, और आयु सत्यापन जैसी तकनीकों को अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, ताकि वे यह समझ सकें कि बच्चों के जीवन में स्क्रीन की भूमिका क्या होनी चाहिए। स्कूलों में डिजिटल नागरिकता की शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। मीडिया और फिल्म जगत को भी यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे बच्चों के लिए सकारात्मक, मूल्य-आधारित और प्रेरक सामग्री का निर्माण करें।

याद रखना चाहिए कि आज के बच्चे कल का समाज तय करेंगे। अगर वे अभी से वर्चुअल दुनिया के भ्रम में खो जाएँगे, तो उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की ताकत नहीं मिल पाएगी। एक ऐसा समाज तैयार होगा जो स्क्रीन पर जीता होगा, लेकिन जीवन की सच्चाईयों से दूर होगा।

बचपन केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, वह मानव जीवन की नींव होता है। अगर उस नींव में सोशल मीडिया की दरारें भर जाएँगी, तो ऊपर खड़ी होने वाली इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकेगी। ऑस्ट्रेलिया ने यह संदेश दुनिया को दिया है कि बच्चों को संरक्षित करना केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र की नीति होनी चाहिए।

भारत को चाहिए कि वह इस चेतावनी को गंभीरता से ले और भविष्य की पीढ़ियों को सिर्फ डिजिटल दक्ष नहीं, बल्कि संतुलित, संवेदनशील और सुरक्षित नागरिक बनाए। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन से थोड़ी दूरी देकर, उनके जीवन में फिर से किताबों, खेलों और संबंधों को जगह दें। वरना, वह दिन दूर नहीं जब बच्चे हमारे साथ नहीं, बल्कि सिर्फ स्क्रीन के साथ बड़े होंगे।

> "अगर बचपन स्क्रीन में खो गया,
> तो समाज खुद अपने भविष्य से रूठ जाएगा।"

2008 मालेगांव बम धमाके के सभी आरोपियों की बरी होने पर गहरी निराशा और चिंता

*आतंकवाद से लड़ाई मजहब या विचारधारा नहीं, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर और समान गंभीरता स किया जाना चाहिए : फ़िरोज़ अहमद, अधिवक्ता

शम्स आगाज

नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत (AIMMM), जो देशभर के मुस्लिम संगठनों का मंच है, 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में सभी आरोपियों के एनआईए अदालत से बरी किए जाने पर गहरी निराशा और गंभीर चिंता व्यक्त करता है। 2008 में मालेगांव में हुआ बम धमाका एक भयावह आतंकवादी हमला था, जिसमें 6 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए थे। यह घटना देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली थी। कई वर्षों की जांच के बाद जिन आरोपियों पर चार्जशीट दायर की गई थी, उनका संबंध कुछ उग्र हिंदुत्ववादी संगठनों से बताया गया — जो एक ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन इतने लंबे ट्रायल के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाना न्याय की विफलता को दर्शाता है। यदि दोषी ये नहीं थे, तो फिर उन बेगुनाहों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? यह फैसला न केवल पीड़ितों को न्याय से वंचित करता है, बल्कि हमारे आपराधिक न्याय तंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मुशावरत के अध्यक्ष, फ़िरोज़ अहमद, अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई मजहब या विचारधारा नहीं, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। पक्षपाती जांच, राजनीतिक दबाव और न्याय में देरी या इंकार — भारत के लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। हम पीड़ितों के परिजनों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हैं और सरकार व एनआईए से मांग करते हैं कि इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाए और न्याय की पुनः स्थापना की जाए। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है लेकिन न्याय को छोड़ देना भारत की आत्मा के लिए संकट है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023